हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 309 बेमेतरा, रविवार 05 जुलाई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

समाचार सार

भारत में जापानी कंपनियों के जीसीसी का दबदबा

नईदिल्ली। जापान के उद्यम भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के विकास में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभर हैं। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। डेलॉयट इंडिया की रिपोर्ट ङ्क इंडियाज स्ट्रेटेजिक जीसीसी प्ले फॉर जापानी एंटरप्राइजेज के अनुसार भारत में जापान के पहले से ही 100 से अधिक केंद्र स्थापित हैं। चूंकि डिजिटल और इंजीनियरिंग की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, इसलिए ये जीसीसी वित्त वर्ष 2030 तक अनुमानित रूप से 470 से 600 अरब डॉलर के आर्थिक प्रभाव की संभावनाएं पेश करेंगे।

आईईएक्स पर 32% महंगी हुई बिजली

नईदिल्ली। देश के सबसे बड़े बिजली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) पर डे अहेड मार्केट (डीएएम) में मार्केट क्लियरिंग प्राइस (एमसीपी) जून 2026 में 32 प्रतिशत बढ़कर 5.2 रुपये प्रति यूनिट हो गया। आईईएक्स ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बिजली की बढ़ती मांग के कारण डीएएम और रियल-टाइम मार्केट (आरटीएम) दोनों खंडों में कीमतों में तेजी आई है। आरटीएम सेगमेंट में औसत मार्केट क्लियरिंग प्राइस महीने के दौरान 4.4 रुपये प्रति यूनिट रही, जो 17 प्रतिशत की वृद्धि है।

फार्मा कंपनियों को सरकार से बड़ी राहत

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने औषधि आदेश, 2013 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। दवा उद्योग का कहना है कि इन बदलावों से नियमों का पालन करना आसान होगा, कंपनियों पर गलत तरीके से अधिक कीमत वसूलने के मामलों में बोझ कम होगा और दवा मूल्य नियंत्रण के नियम पहले से अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। साथ ही, नियमों के पालन को और मजबूत बनाया गया है। 30 जून को सरकार द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, यदि सरकार द्वारा तय नई कीमत लागू होने के बाद कोई मूल्य-नियंत्रित दवा अधिक कीमत पर बेची जाती है।

टेलीग्राम पर सरकार का सख्त, दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

नईदिल्ली। फिल्म और ओटीटी कंटेंट की चोरी (पायरेसी) करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने मशहूर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को एक सख्त नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर की जा रही पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य ऑडियो-विजुअल कंटेंट पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

2 हजार तक पहुंच सकती थी घरेलू सिलेंडर की कीमत, राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन किया

भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबराः पीएम मोदी

बालोतरा (ए)। कल का दिन पूरे मरुधरा के लिए ऐतिहासिक रहा। यह दिन प्रदेश के लिए विकास की नई सौगातें लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल और करीब 79,459 करोड़ रुपये की लागत से विकसित पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रिफाइनरी से जुड़े पेट्रोकेमिकल जोन के विकास की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। इस रिफाइनरी से निकलने वाले उप-उत्पादों (बाय-प्रोडक्ट्स) पर आधारित प्लास्टिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि नया एयरपोर्ट टर्मिनल उड़ान परियोजना के तहत लगभग 480 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इससे मारवाड़ की समृद्ध विरासत और आधुनिक बुनियादी ढांचे के इस अनूठे संगम में देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

पचपदरा रिफाइनरी से जुड़ी खास बातें- करीब 79,459 करोड़ रुपये की लागत से विकसित पचपदरा रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल है। इसके निर्माण के लिए 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई, जो लगभग 15 हजार ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूलों को भरने के बराबर है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह खुदाई मिस्र के गीजा पिरामिड के निर्माण में हुई खुदाई से लगभग छह गुना अधिक है। चलिए यहां बता रहे हैं आज के कार्यक्रम से जुड़ी पीएम मोदी के भाषण की पांच बड़ी बातें।

राजस्थान की धरती के कण-कण ने हमें स्वाभिमान की सीख दी- पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान की धरती के कण-कण ने हमें स्वाभिमान की सीख दी है। यह रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी। आज का दिन इस बात का साक्षी है कि भाजपा की सरकारें केवल परियोजनाओं का शिलान्यास करके उन्हें अधूरा नहीं छोड़तीं, बल्कि उन्हें समय पर पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करती हैं। दो माह पहले यहां हुई दुर्घटना के बावजूद इतनी जल्दी परियोजना का कार्य पूरा होना बड़ी उपलब्धि है।

नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी विकास यात्रा की रफ्तार कम करता है। आज राजस्थान विकास के कई नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

छोटे-छोटे क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा- प्रधानमंत्री ने कहा कि जोधपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

यह टर्मिनल मारवाड़ के विकास को नई गति देगा। उन्होंने बताया कि आज जोधपुर से ही नई उड़ान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत दूर-दराज के छोटे-छोटे क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए भी व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज राजस्थान के 54 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं।

युद्ध के बीच नहीं प्रभावित होने दी घरेलू गैस की कामतें: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। लेकिन 21वीं सदी के नए भारत का संकल्प इस संकट पर भारी पड़ा। हमने हर स्तर पर सही और समयबद्ध फैसले लिए, संकट का सटीक आकलन किया और प्रभावी रणनीति तैयार की। उन्होंने कहा कि इन संवेदनशील निर्णयों का महत्व आने वाला इतिहास अवश्य दर्ज करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी जरूरत की लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी का आयात करता है।

हमने किसानों को 300 रुपये में दी यूरिया

पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण खाद का गंभीर संकट पैदा हो गया था। एक बोरी यूरिया की कीमत 3,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी। इसके बावजूद हमने देश के किसानों को यूरिया मात्र 300 रुपये में उपलब्ध कराया। इसके लिए सरकार ने खजाने से लाखों करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल- पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल-पेट्रोल कोटे में मिलने लग गया। लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं हुए। अफहाएं बहुत फैलाई गई।

भारत की दूसरे देशों के साथ दोस्ती बहुत काम आई

पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ दोस्ती बहुत काम आई। जब ये संकट शुरू हुआ था, उससे पहले भारत 25-26 देशों से ईंधन का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की रणनीति का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए।

खेत में तार लगाते समय करंट की चपेट में आने से मां के साथ दो बेटों की मौत, गांव में पसरा मातम

तखतपुर। बिलासपुर जिले के तखतपुर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भाड़म में एक हृदयविदारक हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और उसके दो पुत्र शामिल हैं। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम भाड़म निवासी दसन बाई सिंगरौल शुक्रवार सुबह अपने खेत में जानवरों के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से लट्ठ तार एवं नायलॉन रस्सी के माध्यम से खेत की घेराबंदी करने गई थीं। उनके साथ उनके दो पुत्र विवेक सिंगरौल (23 वर्ष) और सत्यव्रत सिंगरौल (14 वर्ष) भी मौजूद थे। इसी दौरान तीनों किसी तरह करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मृतका के पति सीताराम सिंगरौल पेशे से चालक हैं, शाम को घर लौटे तो पत्नी और दोनों पुत्र घर पर नहीं मिले। काफी तलाश के बाद जब वे खेत पहुंचे तो वहां पत्नी और दोनों बेटों के शव पड़े मिले। यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए और तत्काल कोटा थाना पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। देर शाम होने के कारण शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। शनिवार को पुलिस ने मर्ग कायम कर तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिए। प्रारंभिक जांच में घटना का कारण करंट लगना सामने आया है। हालांकि, खेत की घेराबंदी के दौरान करंट कैसे प्रवाहित हुआ और हादसे की वास्तविक वजह क्या रही, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

रायपुर में चिंतन शिविर 3.0 का आगाज, विकसित छत्तीसगढ़ के विजन पर होगा मंथन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राजधानी रायपुर स्थित आईआईएम में आज से दो दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। शिविर में मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल की मौजूदगी में विकसित छत्तीसगढ़ के विजन, सुशासन, नीति निर्माण, नवाचार और परिणाम आधारित प्रशासन जैसे विषयों पर व्यापक मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि, उद्योग, निवेश, पर्यटन, खेल, टेक्नोलॉजी और जनसेवा से जुड़े विषयों पर नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी।

तूता में अभी विस्थापन की कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं: NRDA

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर चल रही खबरों के बीच नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में वहां विस्थापन की कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर अभी केवल नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

प्राधिकरण के अनुसार, ग्राम तूता में अतिक्रमण संबंधी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर विधिवत निरीक्षण कराया गया और उसके बाद संबंधित पक्षों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। NRDA ने बताया कि 2 जुलाई को ग्राम के प्रतिनिधियों और समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की। बैठक में यह सहमति बनी कि गांव में सभी पक्षों की बैठक आयोजित कर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद पुनः प्राधिकरण के अधिकारियों से चर्चा कर लोकहित में समाधान निकाला जाएगा। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से भी समय-समय पर गांव के विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में पत्र दिए जाते रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत संबंधित लोगों को प्राथमिक कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि उसका उद्देश्य किसी के साथ अन्याय करना नहीं, बल्कि कानून के अनुसार सार्वजनिक हित में कार्य करना है।

गुजरात में तेज बारिश से बाढ़, 19 लोगों का रेस्क्यू

महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 फीट पानी भरा, दुकानें बंद, जम्मू-कश्मीर में लैंडस्लाइड, रोड बंद

गुजरात (ए)। मानसून देश के सभी राज्यों में पहुंच चुका है। गुजरात में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह तेज बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। गुजरात के मेंडरडा इलाके में समधियाला गांव के पास बाढ़ के पानी में चार गाड़ियां फंस गईं। जिसमें से 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उधर, महाराष्ट्र के भिवंडी में बाजार में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। दुकानें बंद हो गईं। लोग कमर तक डूबकर सड़क पार कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बाद सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के माइनर ओटी में पानी भर गया। यहां से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। मध्य प्रदेश के भोपाल-इंदौर समेत 26 से ज्यादा जिलों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। उज्जैन में पुलिया पार करने की कोशिश में युवक मोटरसाइकिल समेत बह गया। यूपी के 20 जिलों में बारिश हुई। कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया।

पति को निजता का अधिकार, उचित प्रतिबंध भी संभव

नई दिल्ली (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें तलाक के मामले में एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (विवाह-बाह्य संबंध) के आरोपी पति के निजता के अधिकार के दावे को खारिज कर दिया गया था।

अदालत ने कहा कि पत्नी अपने पति पर लगे विवाह-बाह्य संबंध के आरोप को साबित करने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड और होटल बुकिंग से जुड़ी जानकारी जैसे साक्ष्य जुटाने के लिए अदालत की मदद ले सकती है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अलग रह रहे पति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। गुरुवार को अपील खारिज करते हुए पीठ ने कहा, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हमें हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। 10 मई, 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून विवाह-बाह्य संबंध को तलाक का वैध आधार मानता है।

ऐसे में किसी विवाहित पुरुष पर यदि विवाह के दौरान किसी अन्य महिला के साथ यौन संबंध रखने का आरोप है, तो केवल निजता के अधिकार का हवाला देकर उसे कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण या असीमित अधिकार नहीं है।

दुनिया पर छाने को तैयार बॉस बेबी

15 साल के वैभव का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

मैनचेस्टर। आईपीएल 2026 में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट में एक और बड़ी छलांग लगा दी है। आईपीएल 2026 में अपने विस्फोटक प्रदर्शन से इतिहास रचने वाले इस युवा बल्लेबाज ने आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है।

दिल्ली दंगा 2020: कोर्ट ने बड़ी साजिश के मामले में खारिज की जमानत अर्जी

उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका

नई दिल्ली (ए)। 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दीं। अपर सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इन्कार किया। खालिद और इमाम पर आतंकवाद-रोधी कानून और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज है।

खालिद और इमाम ने अपनी अर्ज़ी में कहा कि बिना मुकदमा शुरू हुए लगातार जेल में रखना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इमाम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत से इन्कार के छह महीने बाद भी कार्रवाई में प्रगति नहीं हुई और वह लगभग छह साल से हिरासत में है। खालिद ने भी बिना आरोप तय हुए इतने ही समय से जेल में रहने का हवाला दिया। याचिका में जोर दिया गया कि लंबे समय से जेल में रहने के बावजूद आरोप तय नहीं हुए हैं। खालिद ने तर्क दिया कि बाद की न्यायिक घटनाओं से हालात में बदलाव आया है, जिससे मौजूदा अर्जी सुनवाई योग्य हो गई। उन्होंने आतंक से जुड़े एक मामले में 18 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ज़िक्र किया, जिसने 5 जनवरी के फैसले की आलोचना की थी।

सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियां- सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को बड़ी साजिश वाले मामले में खालिद और इमाम को जमानत देने से इन्कार किया था। हालांकि, सह-आरोपी गुलफिशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को राहत मिली थी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि यूएपीए के तहत खालिद और इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। पीठ ने यह भी कहा कि सभी आरोपियों के साथ भागीदारी के स्तर को देखते हुए एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।

यूएपीए और हिरासत के तर्क- खालिद की अर्जी में मई के एक अन्य मामले में अदालत की टिप्पणियों का उल्लेख था। इन टिप्पणियों में कहा गया था कि यूएपीए के तहत भी जमानत एक नियम है। पीठ ने जोर दिया कि आतंकवाद-रोधी कानून अनिश्चितकालीन हिरासत का जरिया नहीं बनने चाहिए। खालिद ने यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम के.ए. नजीब और वर्नन गोंसाल्विस बनाम महाराष्ट्र राज्य जैसे फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यूएपीए की कानूनी पाबंदियां सांविधानिक सुरक्षा उपायों से ऊपर नहीं हो सकतीं, यदि मुकदमे में उचित समय में पूरा होने की संभावना न हो।

20 से संसद का मानसून सत्र, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (ए)। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने को मंजूरी दे दी है। संसदीय परिपाटी के मुताबिक मानसून सत्र दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी कराई जाएगी। करीब तीन सप्ताह के इस मानसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान में क्या?- केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स हैंडल पर लिखा, भारत सरकार की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र 2026 में संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने की स्वीकृति दे दी है। यह सत्र 20 जुलाई, 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त, 2026 तक चलेगा। रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे।

बजट सत्र में कितना कामकाज हुआ?- इससे पहले संसद का बजट सत्र विगत 18 अप्रैल को समाप्त हुआ था। 28 जनवरी, 2026 को शुरू हुए संसद के बजट सत्र में कई अहम विधेयक पारित कराए गए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक सत्र के दौरान 31 बैठकें हुईं। लगभग 151 घंटे 42 मिनट तक चली कार्यवाही के दौरान कई अहम विधेयकों पर चर्चा कराई गई थी।

किन मुद्दों पर हंगामा कर सकता है विपक्ष?

बीते दिनों मेडिकल की पढ़ाई से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षा- हृश्वश्वञ्ज के पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी विवाद जैसे कई मामले लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में संसद सत्र के दौरान हंगामा होने की आशंका है। इन मामलों के अलावा तृणमूल के दो फाड़ होने का मुद्दा भी चर्चा में है। नजरें स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर टिकी हैं। कांग्रेस अंडमान की ग्रेट निकोबार परियोजना पर भी लगातार हमलावर है।

रायगढ़ की नदियों में 'फ्लाई ऐश' का त्रिवेणी संगम: NGT को चिता की राख से ऐतराज, पर हजारो टनों औद्योगिक राख 'केलों' मे मिलने पर सिस्टम मौन..?

रायगढ़/मूक पत्रिका

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नदियों और जलस्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए चिता की राख तक विसर्जित करने पर एतराज जताता है। लेकिन, रायगढ़ के औद्योगिक इलाकों में इसी हत्रञ्ज के नियमों की चिता रोज जलाई जा रही है। हर साल हज़ारों टन फ्लाई ऐश नदी नालों मे शातिराने तरीके से बहा दिया जाता है और उसी पानी को हम और आप पीते है। अगर आपको इस खुले खेल का 'आंखों देखा सबूत' चाहिए, तो नीचे वीडियो को देखिए। यह बरपाली ग्राम के प्राकृतिक 'बरदे नाले' का वीडियो है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि नाले के दोनों किनारों को फ्लाई ऐश (औद्योगिक राख) से पाट दिया गया है। पानी की प्राकृतिक धार के साथ राख का यह 'धीमा जहर' घुलकर सीधे रायगढ़ की जीवनदायिनी 'केलो नदी' की ओर बह रहा है। यह नजारा किसी त्रिवेणी संगम जैसा लगता है, लेकिन यह आस्था का नहीं, औद्योगिक स्वार्थ का संगम है।

दोबारा से पानी के साथ मिलने फ्लाई ऐश

राख माफिया का नेक्ससः इस बार रूपानाधाम और नवदुर्गा प्लांट पर आरोप-जलस्त्रोतों को खुलेआम तबाह करने का यह दुस्साहस बता रहा है कि उद्योग और ट्रांसपोर्टर्स के हौसले कितने बुलंद हैं। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि नाले में डंप किया गया यह फ्लाई ऐश 'रूपानाधाम' और 'नवदुर्गा' प्लांट का है। बताया जा रहा है कि इस राख को बेखौफतरीके से जलस्त्रोतों में पाटने का ठेका ट्रांसपोर्टर रोहतास नेहरा की फर्म के पास है। जिसने इसे करीब 2 महीने पहले ही डम्प किया है।

8 महीने पुरानी लीपापोती को बरसात ने किया बेनकाब-वीडियो में बहती हुई राख यूं ही नहीं दिख रही है; इसके पीछे प्रशासनिक लीपापोती की एक दिलचस्प कहानी है। करीब 8 महीने पहले जब इस नाले में राख डंपिंग की शिकायत हुई थी, तब वन विभाग और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने मौके पर आकर एक बड़ा 'एहसान' किया था। उन्होंने ठोस समाधान के बजाय, उसके ऊपर सिर्फ मिट्टी का छिड़काव करवा कर मामले को दफ्न कर दिया और रायगढ़ इस्पात और रुपाणा धाम प्लांट पर मामूली जुर्माना के साथ केस क्लोज कर दिया था । लेकिन कुदरत को धोखा नहीं दिया जा सकता। इस बार की बरसात ने उस मिट्टी को धो डाला और अधिकारियों के 'किए-धरे' पर पानी फेरते हुए राख के इस पहाड़ को फिर से बेनकाब कर दिया, जो अब पानी की धार के साथ बहता नजर आ रहा है।

राख की जद में रायगढ़: घर से लेकर पानी तक सब काला-यह सिर्फ एक नाले की त्रासदी नहीं है। गेरवानी, सरायपाली और घरघोड़ा रोड पर दर्जनों छोटे-बड़े उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों से निकलने वाले फ्लाई ऐश का परिवहन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और मुनाफे वाला व्यापार बन चुका है। हालात इतने भयावह हैं कि प्राकृतिक नालों, तालाबों, घरों के आंगनों और यहां तक कि लोगों के सूखते कपड़ों पर भी राख की परत जमी रहती है। ग्रामीण शिकायतें करते हैं, लेकिन कार्रवाई तभी होती है जब मामला मीडिया में उछलता है।

क्या अब जागेगा पर्यावरण विभाग..?-बरदे नाले से बहकर केलो नदी में मिलता यह राखड़ सिर्फप्रदूषण नहीं, बल्कि रायगढ़ के भविष्य के खिलाफएक खुला अपराध है। वीडियो के रूप में पुख्ता सबूत सामने आने के बाद, अब गेंद रायगढ़ जिला प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण मंडल के पाले में है। उन्हें जानकारी भी दे दी गई है। देखना यह है कि क्या इस बार प्लांट प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई होगी, या फिर से नाले में मिट्टी डालकर इस पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाएगी? क्या कागजों पर पर्यावरण बचाने वाला विभाग असलियत में राख माफिया के 'नजराने' के आगे नतमस्तक ही रहेगा?

25 वर्षों से चुनाव नहीं होने और कथित अवैध वसूली पर रजिस्ट्रार सख्त, 17 जुलाई को होगी सुनवाई

बेमेतरा/नवा रायपुर /मूक पत्रिका

कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ में पिछले 25 वर्षों से चुनाव नहीं होने तथा कथित वित्तीय अनियमितताओं और अवैध वसूली की शिकायत पर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ ने संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के लिए 17 जुलाई 2026 को अपराह्न 3 बजे इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में दोनों पक्षों को तलब किया गया है। जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई कोटवार संघ बेमेतरा के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह चौहान द्वारा 9 मार्च 2026 को प्रस्तुत शिकायत के आधार पर की जा रही है। शिकायत में कोटवार एसोसिएशन ऑफछत्तीसगढ़ के वर्तमान अध्यक्ष प्रेमकिशोर बाघ एवं उनकी कार्यकारिणी पर लंबे समय से लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कराने, सदस्यों से कथित अवैध वसूली करने तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।शिकायत में संस्था का विशेष ऑडिट कराने, कथित रूप से अवैध रूप से संचालित कार्यकारिणी को भंग कर निष्पक्ष चुनाव कराने तथा दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता और संबंधित पक्ष को निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। कोटवार संघ बेमेतरा के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि यह लड़ाई प्रदेश के कोटवारों के अधिकारों और पारदर्शी व्यवस्था के लिए लड़ी जा रही है।

नई कानून व्यवस्था से परिचित हुए सरदार वल्लभभाई पटेल स्कूल के विद्यार्थी

रायगढ़/मूक पत्रिका

कानून की जानकारी सबको होना आवश्यक है। इसी तारतम्य में रायगढ़ एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिला पुलिस बल रायगढ़ द्वारा नई कानून व्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रदर्शनी तीन एवं चार जुलाई को नगर निगम ऑडिटोरियम पंजरीप्लांट चक्रधर नगर में जारी है। जिले के समस्त स्कूलों के प्राचार्यों को अपने विद्यार्थियों को कानून व्यवस्था से परिचित कराने हेतु इस प्रदर्शनी में शामिल कराने के लिए कहा गया था। इसी तारतम्य में दिनांक 4 जुलाई 2026 को सरदार वल्लभभाई पटेल शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय रायगढ़ के विद्यार्थियों ने प्राचार्य डॉ. बी. आर. पटेल के नेतृत्व में प्रदर्शनी का दौरा किया तथा नई कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासा वहां उपस्थित अधिकारियों से पूछ कर जानकारी प्राप्त की। एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह सर द्वारा विशेष रूप से विद्यार्थियों को नई कानून व्यवस्था के बारे में विशेष समझाइश दी गई एवं अन्य अधिकारियों द्वारा भी बहुत ही अच्छे तरीके से कानून के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया। उक्त प्रदर्शनी में स्कूल के हायर सेकेंडरी सेक्शन के विद्यार्थियों ने विजिट किया। विद्यार्थियों ने यह दौरा विद्यालय के प्राचार्य डॉ. बी. आर. पटेल, व्याख्याता श्री जे आर नायक एवं शिक्षक श्री कुलदीप पटेल के निर्देशन में किया।

रायगढ़ में फिर 'कोयला खेल' की आहट! अदाणी से लोड गाड़ियों से रास्ते में गायब हो रहा कोयला? रॉबर्टसन साइडिंग पर उठे गंभीर सवाल

सूत्रों का दावा- संगठित नेटवर्क कर रहा खेल, कई लोगों की मिलीभगत की चर्चा; जांच हुई तो खुल सकते हैं बड़े राज

रायगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक जिले रायगढ़ में एक बार फिर कथित कोयला हेराफेरी की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अदाणी क्षेत्र से कोयला लेकर निकलने वाली कुछ टेलर में रास्ते के दौरान कथित रूप से कोयले की मात्रा कम होने की बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में रॉबर्टसन साइडिंग का नाम भी चर्चा में है। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि यह कोई एक-दो लोगों का काम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क के जरिए पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है। दावा है कि पूरे सिस्टम को इतनी गोपनीयता से संचालित किया जाता है कि बाहरी लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर कई स्तरों पर मिलीभगत के कारण यह खेल लंबे समय से चलता आ रहा है रायगढ़ जिला पहले भी कथित कोयला माफियाओं और अवैध कोयला कारोबार को लेकर सुर्खियों में रह चुका है। समय-समय पर कई कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब एक बार फिर सूत्रों के दावों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा है कि कुछ प्रभावशाली लोग पूरे नेटवर्क को अपने प्रभाव के दम पर संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं।

रॉबर्टसन साइडिंग चर्चा के केंद्र में-सूत्र बताते हैं कि सबसे पहले इस तरह की चर्चाएं घरघोड़ा क्षेत्र से सामने आई थीं। अब रॉबर्टसन साइडिंग और उससे जुड़े परिवहन मार्गों को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यदि इन दावों की निष्पक्ष जांच होती है तो पूरे परिवहन तंत्र की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

ऐसे खुल सकता है पूरा खेल-विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोडिंग प्वाइंट से लेकर अनलोडिंग प्वाइंट तक प्रत्येक ट्रक का वेब्रिज रिकॉर्ड, जीपीएस ट्रैकिंग, ई-परमिट, ट्रिप शीट और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो सकता है कि रास्ते में कहीं कोयले की कथित हेराफेरी तो नहीं हो रही। संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है।

जांच की मांग तेज-स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आरोप निराधार हैं तो जांच से सभी संदेह दूर हो जाएंगे, और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों में पारदर्शी जांच से ही जनता का विश्वास कायम रह सकता है।

अब आगे क्या?-यह मामला अभी शुरुआती जानकारी और सूत्रों के दावों पर आधारित है। यदि संबंधित विभाग पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हैं तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हमारी टीम इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है

धरमजयगढ़ के स्द्गष्घ्र प्रभावित क्षेत्र में शेड निर्माण कार्य का तहसीलदार हितेश साहू ने किया निरीक्षण

धरमजयगढ़/मूक पत्रिका

क्षेत्र के में ह्यद्गष्घ्र प्रभावित क्षेत्र दुर्गापुर,शाहपुर में तेजी से हो रहे शेड निर्माण को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तहसीलदार हितेश साहू अपनी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन एवं हाल ही में बने कई शेडों का निरीक्षण किया। शाहपुर के अंतिम छोर पर ज़ब निरक्षण करने अधिकारी और उनकी टीम पहुंचे तब उन्होंने वहा पाया की मौक़े पर 2 ट्रैक्टर में सामान लाकर शेड निर्माण कार्य किया जा रहा था वही उसके किनारे खेतो पर जो शेड बनाया गया था वह मात्र 4 फ़ीट ही ऊंचा था।

मौके पर मिला निर्माण कार्य जारी, कई नए शेड देख प्रशासन भी हुआ सतर्क

निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने पाया कि क्षेत्र में कई स्थानों पर शेड निर्माण का कार्य जारी है। टीम ने उन शेडों का भी निरीक्षण किया जिनका निर्माण हाल ही में पूरा हुआ है। राजस्व अधिकारियों ने निर्माण की स्थिति, स्थान और उससे जुड़े तथ्यों का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार के साथ पटवारी एवं राजस्व विभाग की पूरी टीम मौजूद रही।समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद अधिकारी के निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ा सवाल इन शेडों के निर्माण के उद्देश्य को लेकर सामने आया। प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इन शेडों का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाना है। इसी कारण राजस्व विभाग अब संबंधित तथ्यों, भूमि की स्थिति और निर्माण की वैधानिकता की जांच में जुट गया है। स्थानीय लोगों के बीच भी इन निर्माण कार्यों को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

लगातार प्रकाशित खबरों के बाद हरकत में आया प्रशासन, जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

बताया जा रहा है कि दुर्गापुर-शाहपुर में हो रहे शेड निर्माण को लेकर समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित खबरों के आधार पर उच्च अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और राजस्व विभाग को मौके पर जांच के निर्देश दिए। अब निरीक्षण के बाद तैयार होने वाली रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन के तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।

सिंघौरी स्कूल में लोकतांत्रिक तरीके से हुआ बाल कैबिनेट का गठन

- मतदान कर बच्चों ने चुने शालानायक और कक्षा नायक

बेमेतरा/मूक पत्रिका

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंघौरी में विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराने के उद्देश्य से बाल कैबिनेट का गठन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए शालानायक, उप शालानायक तथा कक्षा नायकों का चयन किया।निर्वाचन प्रक्रिया में संस्था प्रमुख सरस्वती साहू ने पीठासीन अधिकारी, शशिकला यादव ने अधिकारी क्रमांक-1, किरण खरे ने अधिकारी क्रमांक-2 तथा पूनम साहू ने अधिकारी क्रमांक-3 की जिम्मेदारी निभाई। मतदान के दौरान सभी विद्यार्थी अपने पहचान पत्र (आई-कार्ड) के साथ कतारबद्ध होकर मतदान केंद्र पहुंचे। मतदान के बाद प्रत्येक मतदाता की उंगली पर नीली स्याही का निशान भी लगाया गया।मतगणना के बाद ललिता साहू को शालानायक तथा चोकेन्द्र साहू को उप शालानायक निर्वाचित घोषित किया गया।

वहीं कक्षा चौथी से आठवीं तक कक्षा नायक के रूप में हर्षिता, लोकेश, धनराज, चंद्रप्रभा, हिना, वैभव, संध्या, चेतन, उपासना एवं शेखर का चयन हुआ। इसके अलावा विद्यालय के विभिन्न विभागों के लिए भी प्रभारी चुने गए। सांस्कृतिक विभाग में भावना एवं नमिता, स्वास्थ्य विभाग में निधि एवं दिव्या, मध्याह्न भोजन विभाग में रूबी एवं पूजा, पर्यावरण विभाग में टुमेश, टिकेश्वरी एवं केशरी तथा खेल विभाग में अभिषेक एवं सूर्यकांत को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर देवेंद्र साहू, नुतेश्वर चंद्राकर एवं प्रशांत बघेल सहित विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। विद्यालय में आयोजित इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया गया।

रायगढ़ में दिनदहाड़े दबंगई से सनसनी: कोतरा रोड पर युवक की स्विफ्ट कार रोककर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, एसएसपी से न्याय और सुरक्षा की लगाई गुहार

रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ शहर में बदमाशों और असामाजिक तत्वों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, कोतरा रोड इलाके में देखने को मिली है। यहाँ एक युवक पर कुछ दबंगों ने बीच रास्ते में गाड़ी अड़ाकर जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में युवक का दांत टूट गया है और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। प्रार्थी ने मामले की लिखित शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और सिटी कोतवाली पुलिस से करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है मिली जानकारी के अनुसार, कोतरा रोड के लामीदर निवासी मयंक यादव 3 जुलाई को अपनी स्विफ्ट कार क्रमांक छ्त्त-13-रू 8968 से किसी काम के लिए घर से निकले थे। जैसे ही वे घर के पास मोड़ पर पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे सुरजीत सिंह बघेल और रोशन महंत ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर मयंक की कार के आगे बाइक खड़ी कर दी। इसके बाद आरोपियों ने मयंक को जबरन गाड़ी से उतारकर बेदम पीटना शुरू कर दिया।

चीख-पुकार सुनकर जब मयंक की मां और मोहल्ले की अन्य महिलाएं बीच-बचाव करने पहुंचीं, तो आरोपियों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए उनके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की। इस हमले में मयंक का एक दांत टूट गया और सिर में गहरी चोट आई है। घटना के बाद से पूरा पीड़ित परिवार और मोहल्ले के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं।पीड़ित ने एसएसपी को सौंपे आवेदन में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और जानमाल की सुरक्षा की मांग की है। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस इन रसूखदार और बेखौफघूम रहे आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है।

श्रम विभाग में बड़ा घोटाला, भाजपा सरकार कर रही गरीबों के हक से खिलवाड़: ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षा शकुंतला श्रीवास

सारंगढ़-बिलाईगढ़; भाजपा सरकार कर रही गरीबों के हक के साथ खिलवाड़,श्रम विभाग में घोटाला,,,

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में श्रम विभाग और वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफमोर्चा खोलते हुए जनपद पंचायत बरमकेला की सदस्या एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी (महिला मोर्चा) की अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला श्रीवास ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ कागजों और दिखावे के शिविरों तक सिमट कर रह गई हैं, जबकि असल हितग्राही पिछले डेढ़ साल से दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

शिविरों के नाम पर धांधली और दिखावे की राजनीति :- कांग्रेस नेत्री शकुंतला श्रीवास ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा क्षेत्र में शिविर लगाकर भारी धांधली की जा रही है। इन शिविरों के माध्यम से केवल गिने-चुने और चहेते लोगों को चेक बांटकर वाहवाही लूटी जा रही है, जो कि पूरी तरह से एक दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में श्रम विभाग के भीतर एक बड़ा घोटाला पनप रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद श्रमिकों का हक मारा जा रहा है।

इन प्रमुख योजनाओं में आ रही हैं गंभीर शिकायतें :-शकुंतला श्रीवास ने विभाग की उन प्रमुख योजनाओं को रेखांकित किया, जिनमें हितग्राहियों को लंबे समय से लाभ नहीं मिल पा रहा है:

मिनीमाता महतारी जतन योजना: इसके तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 20,000 रुपए की राशि दी जानी है। आरोप है कि डेढ़ साल से महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला है और गरीब महिलाएं अपने हक के पैसों के लिए भटक रही हैं।

मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना व गणवेश/पुस्तक योजना: श्रमिकों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक की सहायता राशि का प्रावधान है, लेकिन यह भी अधर में लटका है।

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना: 59 से 60 वर्ष के बुजुर्ग श्रमिकों को मिलने वाली 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि से भी कई बुजुर्ग वंचित हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (क्क्ररू-स्ङ्घरू): 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने वाली इस योजना का क्रियान्वयन भी लचर है।

जांच और नवीनीकरण ठप, डेढ़ साल से लंबित हैं आवेदन:- जनपद सदस्या ने आक्रोश जताते हुए कहा कि साइकिल सहायता योजना, प्रसूति योजना और मृत्यु सहायता योजना जैसे संवेदनशील मामलों की न तो कोई जांच की जा रही है और न ही कार्डों का नवीनीकरण हो रहा है। उन्होंने बताया:

÷क्षेत्र के सैकड़ों गरीब श्रमिकों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए बकायदा फॉर्म भरे हैं। फॉर्म भरे हुए डेढ़ साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक विभाग द्वारा उनका निराकरण नहीं किया गया। भाजपा सरकार श्रम विभाग के नाम पर गरीबों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है।÷

निष्पक्ष जांच की मांग :- ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि श्रम विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया और लंबित पड़े आवेदनों का तुरंत निराकरण कर महिलाओं व श्रमिकों को उनका हक नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी श्रमिकों के हित में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उन्होंने शासन-प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

खरीफसीजन में कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त, बेमेतरा में अवैध उर्वरक भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 275 बोरी यूरिया जब्त

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर उड़नदस्ता दल की छापामार कार्रवाई, दोषियों पर होगी कड़ी वैधानिक कार्रवाई

बेमेतरा/मूक पत्रिका

खरीफ सीजन 2026 के दौरान किसानों को निर्धारित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशानुसार तथा कृषि विभाग के उप संचालक श्री मोरध्वज डडसेना के मार्गदर्शन में गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा जिलेभर में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध लगातार औचक निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर उड़नदस्ता दल ने ग्राम जानो, तहसील देवकर में अँजोर वर्मा के परिसर में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 275 बोरी यूरिया अवैध रूप से भंडारित पाया गया। मौके पर समस्त उर्वरक को विधिवत जब्त कर लिया गया है तथा संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। प्राप्त जवाब के परीक्षण के उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग द्वारा जब्त उर्वरकों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को केवल मानक गुणवत्ता वाले उर्वरक ही उपलब्ध हों।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण एवं निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि कोई निजी कृषि केंद्र, विक्रेता अथवा सहकारी संस्था इस प्रकार की अनियमितता करते हुए पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी परिस्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रशासन द्वारा पूरे जिले में सतत निगरानी रखी जा रही है तथा शिकायत प्राप्त होते ही बिना पूर्व सूचना के तत्काल जांच एवं छापामार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने किसानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री अथवा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिले तो इसकी सूचना कृषि विभाग अथवा जिला प्रशासन को दें। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

धरमजयगढ़ में 'कानफोड़ू' साइलेंसर का खेल बेखौफ! Sp साहब के आदेश का नहीं पड़ रहा असर, यहां खुलेआम फिटिंग और प्रचार–आखिर कार्रवाई कब?

धरमजयगढ़/रायगढ/मूक पत्रिका

एसएसपी शशिमोहन सिंह द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा और मॉडिफाई साइलेंसर पर कार्यवाही की जा रही पर यह कार्यवाही मात्र रायगढ़ में ही देखने को मिल रहा हैं धरमजयगढ़ मानों इस कार्यवाही से कोशो दूर हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहें क्युकी यहां मॉडिफाई सायलेंसर लेकर सडक पर चलना तों दूर उल्टा इंस्टाग्राम पर इसका खुलेआम प्रचार प्रसार किया जा रहा और यह मोटरसाइकल दिन भर लोगों को परेशान कर रहा पर इसको पुलिस पकड़ तक नहीं पा रही। यहां न केवल मॉडिफाई साइलेंसर वाली बाइक सड़क पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं, बल्कि इन्हें लगाने का कारोबार भी खुलेआम चलता दिखाई दे रहा है। इन जैसे लोगों नें आम जनता को परेशान कर रखा हैं। इससे लोगों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या धरमजयगढ़ में नियमों का पालन कराने वाला कोई नहीं है क्या इस वाहन और इस जैसे सभी वाहनों को पुलिस जप्त करेगी या नहींज? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक गैरेज संचालक खुद मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर उसका प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में वह इसकी तेज, ÷कानफोड़ू÷ आवाज को ही इसकी खासियत बताकर प्रचार करता नजर आता है। यदि वायरल वीडियो वास्तविक है, तो यह केवल मोटर व्हीकल नियमों की अनदेखी ही नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने जैसा भी माना जा सकता है। इसके बाद अब लोगों की नजर संबंधित विभाग की कार्रवाई पर है।

बच्चों-बुजुर्गों की परेशानी, कार्रवाई का इंतजार- धरमजयगढ़ के कई मोहल्लों और बाजारों में तेज आवाज वाले मॉडिफाई साइलेंसर लोगों के लिए रोज की परेशानी बन चुके हैं। स्कूलों के आसपास, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों से गुजरते समय ऐसी बाइकों की तेज आवाज से छोटे बच्चे, बुजुर्ग और आम नागरिक परेशान होते हैं। अब सवाल यह है कि रायगढ़ की तरह धरमजयगढ़ में भी क्या विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों और मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वाले गैरेज संचालकों पर कार्रवाई होगी, या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा?

यूनियन की मांग पर निकाय के सफाई कर्मियों को मिला सुरक्षा उपकरण

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ :- कांकेर नगर पालिका में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों में नगर पालिका कांकेर ने सफाई कर्मियों को आज उनके सुरक्षा उपकरण वितरित किया है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय कर्मचारी यूनियन के इकाई महासचिव दिलीप साहू ने आज एक प्रेस बयान जारी कर बताया। साहू ने बताया कि कर्मचारी यूनियन द्वारा नगर पालिका अधिकारी को 7 दिन पहले मांग किया गया था कि निकाय में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को बरसाती, बरसाती जूता, हाथ के दस्ताने एक जुलाई तक वितरित किया जाना चाहती। नगर पालिका अधिकारी ने यूनियन की मांगों को स्वीकार करते हुए आज सफाई कर्मचारियों को बरसाती, हाथ का दस्ताना, बरसाती जूता वितरित की गई है। यूनियन नेता ने इसे यूनियन की एक जीत के रूप से निरूपित करते हुए सफाई कर्मचारियों को बताया कि यह अभी आंशिक जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अभी साप्ताहिक अवकाश का मांग किया गया है, उसे भी अमल कराने की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को अपनी एकजुटता बनाए रखने का अपील किया है।

कोटवारों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 11 सूत्रीय ज्ञापन, मानदेय वृद्धि व नियमितीकरण की उठाई मांग

कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने वेतन विसंगति, नियुक्ति नियम और अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न पर जताई नाराजगी

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ :-चरामा कांकेर कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ की तहसील शाखा चरामा द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम तहसीलदार के माध्यम से 3 जुलाई 2026 को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश के कोटवारों की वर्षों से लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए शासन से शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के कोटवार लंबे समय से नियमितीकरण, उचित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। संगठन का कहना है कि अल्प मानदेय के कारण कोटवारों के परिवारों का भरण-पोषण कठिन हो गया है तथा वृद्धावस्था में भी उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने कोटवारों का नियमितीकरण करते हुए अन्य राज्यों की तर्ज पर शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने, सेवा भूमि के आधार पर वर्तमान मानदेय में बढ़ोतरी करने तथा ए, बी, सी और डी श्रेणी के कोटवारों का मासिक मानदेय क्रमशः 15 हजार, 12 हजार, 10 हजार और 8 हजार रुपये किए जाने की मांग रखी है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि मृत कोटवारों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों के अनुरूप हो तथा अधिकारियों द्वारा कथित रूप से की जा रही अनावश्यक ड्यूटी, बेवजह प्रताड़ना और झूठे आरोपों पर रोक लगाई जाए। संगठन ने शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर बिना तथ्य किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने की मांग भी की है। कोटवार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के कोटवार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन जिला अध्यक्ष एवं तहसील शाखा पदाधिकारियों के हस्ताक्षर सहित शासन को प्रेषित किया गया।

रक्तदान अभियान को मिलेगी नई गति, जगदलपुर और बकावंड ब्लॉक की कार्यकारिणी गठित, रेडक्रॉस सोसाइटी ने पदाधिकारियों की घोषणा की, गांव-गांव तक रक्तदाता नेटवर्क बनाने पर रहेगा जोर

जगदलपुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला बस्तर ने स्वैच्छिक रक्तदान को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जगदलपुर एवं बकावंड ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का गठन किया है। नवगठित टीमों का उद्देश्य जिले में रक्तदान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना, नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करना तथा जरूरतमंद मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने के लिए मजबूत रक्तदाता नेटवर्क तैयार करना होगा।बस्तर कलेक्टर एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष आकाश छिकारा के मार्गदर्शन तथा सचिव एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय बसाक के निर्देशानुसार ब्लड बैंक समिति के अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम ने दोनों ब्लॉकों की कार्यकारिणी की घोषणा की।जगदलपुर ब्लॉक में बी. प्रसाद राव को अध्यक्ष एवं ओम साहू को सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं बकावंड ब्लॉक की जिम्मेदारी श्याम बघेल को अध्यक्ष तथा प्रकाश जोशी को सचिव के रूप में सौंपी गई है। दोनों ब्लॉकों में उपाध्यक्ष, संयोजक और सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है।ब्लड बैंक समिति के अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। नई कार्यकारिणियां गांव-गांव तक रक्तदान जागरूकता अभियान चलाएंगी और युवाओं, सामाजिक संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे जोड़ने का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य ऐसा तंत्र विकसित करना है, जिससे जिले में किसी भी जरूरतमंद को रक्त के अभाव का सामना न करना पड़े।

इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्लड बैंक समिति के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर एम. चेरियन, चेयरमैन मनीष गुप्ता, वाइस चेयरमैन नरेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष ऋषि भटनागर सहित अन्य पदाधिकारियों ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए रक्तदान अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

जगदलपुर ब्लॉक कार्यकारिणी

अध्यक्षः बी. प्रसाद राव

उपाध्यक्षः गजेंद्र सेठिया, दिव्य साहू, बृजेश कपूर, नीलम कुशवाहा

सचिवः ओम साहू

संयोजकः वीरेंद्र शर्मा, ज्योति पटवा, घनश्याम नाग, भागीरथी प्रसाद मौर्य

सदस्यः लक्ष्मी देवांगन, संगीता साहू, नितेश पटेल, राजपाल सिंह, मोहम्मद अल्ताफ, हिमांशु मिश्रा

बकावंड ब्लॉक कार्यकारिणी

अध्यक्षः श्याम बघेल

उपाध्यक्षः खुसवंत पांडे, फालगुनी पटेल, फुलमनी कश्यप, लूपतेश्वर पाणिग्रही

सचिवः प्रकाश जोशी

संयोजकः हेमंत नाग, पूनम कश्यप, भीमबती नाग, नूतन राम कर्मा, प्रभु चरण यादव

सदस्यः डमरू मंडावी, दीपक सिंह बिसाई, गोपाल गरेंगा, हेमलाल आचार्य, कमल पटेल

संरक्षकः किशोर पांडे, नीलकुमार बघेल

सहकारिता सप्ताह के तहत कोसीर समिति में हुआ वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

कोसीर/मूक पत्रिका

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कोसीर (पंजीयन क्रमांक 1561) के परिसर में शनिवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में अधिकारियों, समिति कर्मचारियों और किसानों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास का संदेश दिया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त सहकारिता एवं नोडल अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ कामेश सिंह कश्यप ने पौधरोपण करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते पर्यावरणीय संकट के दौर में प्रत्येक व्यक्ति का अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनकी नियमित देखभाल करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां केवल किसानों को कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने तक सीमित न रहें, बल्कि पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर सहकारिता निरीक्षक लकेश्वर देवांगन, समिति प्रबंधक खगेश जांगड़े, समिति के कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे। सभी ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करने का माध्यम हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की अमूल्य धरोहर भी हैं। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

उफनते नाले में बह गई बाइक, बाल-बाल बची युवक की जान; हिर्री-सहजपाली मार्ग पर बड़ा हादसा टला

बरमकेला/मूक पत्रिका

लगातार हो रही बारिश के चलते बरमकेला विकासखंड के ग्राम हिर्री और सहजपाली के बीच स्थित नाले में शनिवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तेज बहाव के बीच मोटरसाइकिल सहित नाला पार करने का प्रयास कर रहे एक युवक की जान तो बच गई, लेकिन उसकी बाइक उफनते पानी में बह गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मार्ग पर स्थायी समाधान की मांग की है। प्रत्यक्षदर्शियों एवं स्थानीय लोगों के अनुसार, लगातार बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव अचानक काफी तेज हो गया था। इसी दौरान एक युवक अपनी मोटरसाइकिल लेकर नाला पार करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह बीच धार में पहुंचा, पानी के तेज बहाव ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वह बाइक सहित बहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं और हर कोई अनहोनी की आशंका से सहम गया। ग्रामीणों के अनुसार युवक पानी के तेज बहाव में कुछ दूर तक बहता चला गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह स्वयं को संभालते हुए सुरक्षित बाहर निकल आया। हालांकि उसकी मोटरसाइकिल तेज बहाव की चपेट में आकर पानी में बह गई। युवक के सुरक्षित बच जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन घटना ने बरसात के मौसम में उफनते नालों को पार करने के खतरों को एक बार फिर उजागर कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नाले का तेज बहाव साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो में लोग युवक को बहते देख चिंतित नजर आ रहे हैं। घटना के बाद आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि युवक कुछ और देर तक बहाव में फंसा रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने बताया कि हिर्री-सहजपाली मार्ग का यह नाला हर वर्ष बारिश के मौसम में उफान पर आ जाता है। पानी बढ़ते ही दोनों गांवों के बीच संपर्क लगभग टूट जाता है। इसके बावजूद आवश्यक कार्य, रोजगार, खेती-बाड़ी और अन्य जरूरतों के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से आवागमन करना पड़ता है। कई बार छोटे-बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस स्थान पर शीघ्र स्थायी पुल या ऊंची पुलिया का निर्माण कराया जाए, ताकि बरसात के दिनों में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार न करना पड़े। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। यह घटना एक बार फिर प्रशासन और आम लोगों दोनों के लिए चेतावनी है कि बारिश के दौरान उफनते नालों और पुल-पुलियों को पार करने में जरा-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञ भी लगातार ऐसे हालात में पानी का स्तर कम होने तक इंतजार करने और जोखिम उठाकर नाला पार नहीं करने की सलाह देते हैं।

÷शनिवार को उफनते नाले में एक बाइक बहने की घटना सामने आई। बाइक चालक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। बरसात के दिनों में यह नाला हमेशा खतरा बना रहता है। प्रशासन को यहां स्थायी समाधान करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।÷

- सत्या घनश्याम ईजारदार
सरपंच, ग्राम पंचायत सहजपाली

÷कल एक व्यक्ति उफनते नाले में बहते-बहते बचा। नाले पर बनी पुलिया काफी छोटी है। हर वर्ष बरसात के मौसम में जलस्तर पुलिया के ऊपर पहुंच जाता है, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ हादसों का खतरा भी बना रहता है। क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को देखते हुए यहां शीघ्र उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण कराया जाना चाहिए।÷

भोजमती सिदार
सरपंच, ग्राम पंचायत हिर्री

संपादकीय

हिंद प्रशांत में संतुलन की नई धुरी बने भारत-जापान

भारत और जापान ने अपने विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी संबंधों को नई मजबूती देते हुए नई दिल्ली में आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने साफ संकेत दिया कि बदलते वैश्विक हालात के बीच भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दूसरे के भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बनकर उभर रहे हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी करते हुए संबंधों को और गहरा करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची को अपनी 'छोटी बहन' बताते हुए भारत और जापान के बीच बौद्ध सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया, विशेषकर जापान के नारा प्रांत से भारत के ऐतिहासिक जुाव को रेखांकित किया। वहीं ताकाइची ने भी मोदी को अपना 'बड़े भाई' बताया और कहा कि दोनों देशों के संबंध अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग रहा। दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त वक्तव्य जारी किया और भारतीय तथा जापानी संस्थानों के बीच कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की सूक्ष्म तकनीकी क्षमता और भारत की साफ्टवेयर विशेषज्ञता का मेल वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास को नई दिशा देगा। यह सहयोग केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेजी से भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत और जापान ने अपने पहले संयुक्त रक्षा विकास परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली 'यूनिकॉर्न' के सह विकास से संबंधित है। इस समझौते को हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

आज का राशिफल

मेष राशि :- धन का व्यय संभव है, तनाव पूर्ण वार्ता से बचिएगा, कार्य का ध्यान अवश्य रखें।

वृष राशि :- अधिकारियों के समर्थन से सफलता, कार्य कुशलता से संतोष होवे, बिगड़े कार्य बनेंगे।

मिथुन राशि :- चिन्ताएं कम हो, सफलता के साधन जुटाए तथा शुभ समाचार अवश्य मिलेंगे।

कर्क राशि :- बड़े-बड़े लोगों से मेल मिलाप होवे तथा सुख समृद्धि के साधन अवश्य बनेंगे।

सिंह राशि :- स्त्रीवर्ग से हर्ष उल्लास होवे, भोग कार्य की प्राप्ति होगी, कार्य गति उत्तम बनें।

कन्या राशि :- प्रतिष्ठा बाल बाल बचें, संघर्ष से अधिकार प्राप्त करें, भाग्य का साथ दें।

तुला राशि :- कुटुम्ब और धन की चिन्ता बनी रहे, परिश्रम से सोचे कार्य अवश्य ही बनेंगे, ध्यान दें।

वृश्चिक राशि :- प्रत्येक कार्य में बाधाएं, क्लेश युक्त रखे, स्थिति साम्यर्य के योग अवश्य बनें।

धनु राशि :- भावनाएं विक्षुब्ध रखे, दैनिक कार्यगति मंद रहे, परिश्रम से कार्य अवश्य बनेंगे।

मकर राशि :- तनाव क्लेश व अशांति, धन का व्यय, मानसिक खिन्नता, अवश्य बनेगी।

कुंभ राशि :- कार्य कुशलता से संतोष, व्यवसायिक समृद्धि के साधन।

मीन राशि :- कुटुम्ब के कार्यों में समय बीतें तथा हर्षप्रद समाचार प्राप्त हो।

जीवन का माधुर्य मानवता का प्रकाश

भगवान महावीर ने मानव जीवन का सबसे बड़ा संदेश मानवता को माना है। उनका स्पष्ट कथन था कि मनुष्य सबसे पहले मानवता को अपने जीवन में धारण करे, क्योंकि मानवता ही जीवन का वास्तविक माधुर्य है। जिस प्रकार एक फूल बिना किसी को बुलाए अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को महका देता है और भौंरे स्वयं उसकी ओर आकर्षित होकर चले आते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर मानवता के गुण विकसित हो जाते हैं, उसका जीवन अपने आप समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। वह केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का कल्याण करने वाला बन जाता है। मानवता का अर्थ केवल मनुष्य का शरीर धारण करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार, वाणी और कर्मों में प्रेम, करुणा, दया, विनम्रता और सेवा की भावना को विकसित करना है। यही गुण जीवन को मधुर बनाते हैं और मनुष्य को सच्चे अर्थों में महान बनाते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने मन, वाणी और इन्द्रियों जैसी अमूल्य शक्तियाँ प्रदान की हैं। इनका उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मविकास और समाजहित में उनका सदुपयोग करना है। यदि मन शुभ विचारों से भरा होगा, वाणी मधुर होगी और इन्द्रियाँ संयमित होंगी तो जीवन स्वत: सार्थक बन जाएगा। इसके विपरीत यदि मन ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार से भर जाए तो मनुष्य का जीवन अशान्ति और संघर्ष का कारण बन जाता है। शरीर से मनुष्य होने के बावजूद यदि उसकी सोच हिंसक, स्वार्थी और क्रूर हो जाए तो वह मानवता से दूर होकर पाशविक प्रवृत्तियों का शिकार बन जाता है। तब उसके भीतर भेड़िए की आक्रामकता, सर्प की विषैली प्रवृत्ति और कुत्ते जैसी लड़ाकू मानसिकता दिखाई देने लगती है। भगवान महावीर का संदेश है कि मनुष्य समय-समय पर अपने भीतर झाँके और देखे कि कहीं ऐसी प्रवृत्तियाँ उसके जीवन में तो प्रवेश नहीं कर रही हैं। मानवता का सबसे महत्वपूर्ण आधार भद्रता और सरलता है। आज के समय में सरल और निष्कपट व्यक्ति को अक्सर मूर्ख समझ लिया जाता है, जबकि वास्तविक महानता उसी में निहित है। जो व्यक्ति छल, कपट और दंभ से मुक्त होकर बालक की तरह निर्मल हृदय रखता है, वही सच्चा भद्र मनुष्य कहलाता है। लेकिन केवल सरल होना ही पर्याप्त नहीं है। उसके साथ विवेक का प्रकाश भी आवश्यक है। विवेक मनुष्य को सही और गलत का अंतर समझाता है तथा उसे उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि सरलता के साथ विवेक जुड़ जाए तो जीवन संतुलित और सफल बन जाता है। मानव जीवन में विनय का विशेष महत्व है। भगवान महावीर ने धर्म का मूल ही विनय को बताया है। विनम्रता मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाती है। अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, वह जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार हीरा सोने में जड़ा जाता है क्योंकि उसमें लचीलापन होता है, उसी प्रकार अहिंसा, सत्य, दया, प्रेम और करुणा जैसे महान गुण उसी व्यक्ति के जीवन में स्थान पाते हैं, जिसके भीतर विनम्रता होती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को सोने के समान विनम्र और मूल्यवान बनाना चाहिए। हालांकि भगवान महावीर यह भी बताते हैं कि दिखावटी नम्रता से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अक्सर झुककर ही दूसरों को धोखा देता है। इसलिए विनय के साथ विवेक का होना भी आवश्यक है। अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता था और इसी अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। इसके विपरीत विनम्र व्यक्ति निरंतर सीखता है, आगे बढ़ता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता है और दूसरों के हित को अपने हित से ऊपर रखता है, उसका जीवन वास्तव में सफल माना जाता है। मानवता का अर्थ केवल अच्छे विचार रखना नहीं, बल्कि उन्हें व्यवहार में उतारना भी है। मानवता की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति भावना की पवित्रता में दिखाई देती है। मासखमण के एक तपस्वी संत के सामने एक निर्धन बालक का प्रसंग इसका अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

दिल्ली: वायु प्रदूषण के साथ ओजोन प्रदूषण की चुनौती

- ललित गर्ग

राजधानी दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण की भयावह समस्या से जूझती रही है। हर सर्दी में धुंध की मोटी चादर, जहरीली हवा और दमघोंटू वातावरण राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते हैं। अब तक इस संकट की चर्चा मुख्यत: पीएम 2.5, पीएम 10, पराली और वाहनों के धुएँ तक सीमित रही, लेकिन अब एक नया और अधिक खतरनाक खतरा तेजी से उभरकर सामने आया है-भूतलीय (ग्राउंड लेवल) ओजोन प्रदूषण। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, जयपुर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद जैसे शहर भी ओजोन प्रदूषण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके दुष्प्रभाव धीरे-धीरे मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण को भीतर तक बीमार कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को भी अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर दिया जाता है। कभी किसानों की पराली को संपूर्ण दोषी ठहरा दिया जाता है तो कभी केवल वाहनों को। जबकि वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक है। यदि समस्या की जड़ तक पहुँचना है तो अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, ऊर्जा उपभोग की वर्तमान व्यवस्था और विकास के मौजूदा मॉडल पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा।

दिल्ली आज केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रदूषण हॉटस्पॉट भी बन चुकी है। गर्मियों में बढ़ते तापमान, तेज धूप और वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से भूतलीय ओजोन बनती है। यह वही ओजोन नहीं है जो वायुमंडल की ऊपरी परत में पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। धरातल पर बनने वाली ओजोन एक विषैली गैस है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता कम करती है, दमा के रोगियों की स्थिति बिगाड़ती है, आँखों में जलन पैदा करती है तथा हृदय रोगों का जोखिम बढ़ाती है। आज दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग सांस लेने में कठिनाई, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें ओजोन प्रदूषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसे निर्णय निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन केवल वाहन नीति से समस्या का समाधान संभव नहीं है।

वास्तविक संकट अनियोजित शहरीकरण का है। पिछले दो दशकों में दिल्ली और उससे लगे क्षेत्रों में जिस तेजी से खेत, तालाब और हरित क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में बदले हैं, उसने प्राकृतिक संतुलन को गहरा आघात पहुँचाया है। जहाँ कभी वर्षा का पानी धरती में समा जाता था, वहाँ अब सीमेंट और डामर की सतह है। पारंपरिक जलस्रोत मिट गए, पेड़ों की संख्या घटी और गर्मी बढ़ती गई। यही कारण है कि शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक रहने लगा है। यही अतिरिक्त गर्मी ओजोन बनने की प्रक्रिया को और तेज करती है। आज महानगरों का विस्तार विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है। शहरों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, आवास चाहिए, उद्योग चाहिए। इन सबके लिए खेत समाप्त हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और जलस्रोत नष्ट हो रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रदूषण केवल हवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल, मिट्टी और जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। विकास की यह दिशा अंतत: मानव जीवन के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है। दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और गुणवत्ता अभी भी इतनी प्रभावी नहीं हो सकी कि लोग निजी वाहनों का त्याग करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना स्वागतयोग्य है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि बिजली यदि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से आएगी तो प्रदूषण केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित परिवहन को समानांतर गति से बढ़ाना आवश्यक है। ओजोन प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ओजोन फसलों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर उत्पादन घटा देती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मानसून और बढ़ती गर्मी पहले ही किसानों के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ओजोन प्रदूषण कृषि संकट को और गहरा कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किंतु अब समय आ गया है कि इसकी रणनीति का विस्तार किया जाए। केवल पार्टिकुलेट मैटर पर ध्यान देने के बजाय ओजोन जैसे द्वितीयक प्रदूषकों की निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रण पर भी समान बल देना होगा। वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र को अधिक व्यापक, आधुनिक और पारदर्शी बनाना होगा। समस्या के समाधान में नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कचरा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, खुले में ईंधन जलाना, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे का अनुचित निस्तारण जैसी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, साइकिल और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा।

अच्छी तरह परख लीजिए आपकी महबूबा किसी की बाबू तो नहीं?

- मनोज कुमार अग्रवाल

पुणे के लोहगढ़ में ट्रेकिंग पथ पर केतन अग्रवाल के मर्डर ने समूचे समाज को समाज में पल रहे लव अफेयर्स और उनके घातक परिणामों के प्रति चेताया है कि शादी के लिए वधू का चयन करने से पहले जांच लीजिए आपकी होने वाली महबूबा के जीवन में कोई दूसरा तो नही है अच्छी तरह परख लीजिए कि वह किसी की बाबू तो नहीं है? दरअसल समाज में जैसे जैसे लड़कियों के स्वछंद उन्मुक्त जीवन का चलन बढ़ा है लव अफेयर्स डेटिंग और ब्रेकअप का सिलसिला भी चल रहा है लेकिन अभिभावक अभी भी पुराने परम्परागत चलन से लडके लड़कियों का वर वधू के लिए चयन कर रहे हैं कई बार माता पिता परिवार के दबाव में आकर लड़किया अपने प्रेमी के इतर विवाह के लिए राजी हो जातीं हैं तो की बार प्रेमी के साथ साजिश कर विवाह से पहले या बाद में मंगेतर या पति को मौत के मुंह में धकेल रहीं हैं। दरअसल इंदौर की सोनम मेरठ की मुस्कान और अब पुणे की सिया ये बदलते दौर और बदलते चरित्र के किरदार हैं जिस समाज में लडकियों को मासूम अबला नादान समझा जा रहा है और कानून भी जिन्हें संरक्षण देता रहा है उस समाज में मासूम चेहरे के पीछे छिपी कुटिलता अपराध करने की मानसिकता और समाज लोकलाज पुलिस कानून का तनिक भी भय नहीं होना बदलते परिवेश को बयान कर रहा है ऐसे में जरूरी है कि युवाओं को अपने जीवन साथी का चयन बहुत सोच समझकर और उसके आचरण पिछले जीवन और संबन्धों की पड़ताल करने के बाद किया जाए। केतन अग्रवाल के परिवार ने एक बारहवीं फेल स्वछंद आचरण वाली लड़की की बिना जरूरी पड़ताल किए सिर्फ सिया के परिवार की बात पर भरोसा किया इस का भुगतान एक मासूम होनहार शिक्षित बिजनेस मैन युवा को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा यदि केतन या उसका परिवार जरा सा भी सजग होता तो सिया की हरकतों से पहले ही वाकिफ हो जाता और सतर्कता अपना लेता या यह रिश्ता ही नहीं बनता।

बहन के शक ने खोला राज वरना पुलिस खा गयी थी गच्चा

अंतिम संस्कार के बाद का मोड़ ऐसा मोड़ आया कि कहानी ही पलट गयी। केतन की मौत को शुरुआत में एक हादसा (लोहागढ़ किले की खाई में गिरना) माना जा रहा था. पुलिस ने भी सिया की बुनी कहानी पर सहज भरोसा कर लिया था केतन का परिवार भी बेचारी कह कर उलटा सिया ऐ फर्जी आंसू पौंछ रहा था लेकिन मौत के 4 दिन बाद जब सिया केतन के घर पहुंची, तो केतन की बहन ने उससे उस दिन की घटना के बारे में पूछा.सबसे पहली बार उसे सिया के चेहरे के भाव और बयान में विरोधाभास नजर आया उसने परिवार और पुलिस को चेताया।

आपको बता दें कि पुणे के हालिया हत्याकांड मामले में पुलिस जांच के दौरान कई गंभीर खुलासे हुए हैं। इस मामले में मुख्य आरोपियों द्वारा की गई लंबी प्लानिंग ने सुरक्षा विशेषज्ञों और जांच अधिकारियों को हैरान कर दिया है।डिजिटल सबूतों से मिली मदद पुलिस जांच के अनुसार, घटना से पहले के छह महीनों में डिजिटल संचार रिकार्ड से चौंकानेवाला खुलासा हुआ कि सिया चेतन चौधरी के साथ संबन्धों में थी।

जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य घटना से पहले भी पीड़ित पर हमला करने का प्रयास किया गया था। लोहगढ़ किले के पास हुई एक पिछली घटना के दौरान पीड़ित की जान बाल-बाल बची थी, जिसे उस समय एक दुर्घटना के रूप में पेश किया गया था।

आपको बता दें कि साजिश के मामले में सिया और चेतन इंदौर के राजा रघुवंशी हत्या कांड की सोनम से भी आगे निकले। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. 26 साल के बिजनेसमैन और रियल एस्टेट डायरेक्टर केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में एक सामान्य ट्रेकिंग हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में जो सच सामने आया है, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं. केतन की मंगेतर सिया गोयल (20 साल) ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी (22 साल) के साथ मिलकर इस खौफनाक मर्डर को अंजाम दिया।

दिल्ली मेट्रो का फैसला- बढ़ जाएगी यात्रियों की परेशानी

संतोष कुमार पाठक

दुनिया भर के विकसित देशों के विकास की कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। बेहतर सड़क और शानदार सार्वजनिक परिवहन (बस, मेट्रो, ट्रेन आदि) व्यवस्था। कई मायनों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर सरकार द्वारा किए गए खर्च को बड़ा निवेश ही माना जाता है क्योंकि दशकों तक इसका फायदा उस देश की अर्थव्यवस्था को मिलता रहता है। भारत जैसे देश के लिए बेहतर, सुगम और तेज रफ्तार वाली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो और भी जरूरी है क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और गैस के आयात पर ही खर्च होता है। तमाम दावों के बीच कड़वी सच्चाई तो यही है कि भारत पेट्रोल-डीजल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और हमारी निर्भरता किस हद तक है, इसका अंदाजा ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई के असर के रूप में हम सबको दिख ही गया है। भारत के लगभग हर शहर में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है लेकिन सार्वजनिक परिवहन की लचर व्यवस्था के कारण लोग उससे भी ज्यादा तेजी से पर्सनल गाड़ियां खरीदते हैं और नतीजा हर तरफ ट्रैफिक जाम यानी पेट्रोल-डीजल और गैस की बर्बादी। दिल्ली में भी मेट्रो का तेजी से विस्तार तो हो रहा है लेकिन यह दिल्ली की जरूरतों के लिहाज से अभी भी काफी पीछे है। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नकारते हुए दिल्ली मेट्रो में इसकी शुरुआत के समय ही यह फैसला किया गया था कि स्टूडेंट्स, बुजुर्ग और पत्रकार सहित किसी भी कैटेगरी में किसी को भी रियायती दरों पर कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। थोड़े बहुत विरोध के बाद सबने इसे स्वीकार कर लिया जबकि दिल्ली की सरकारी परिवहन व्यवस्था यानी डीटीसी बसों में कई कैटेगरी के यात्रियों को रियायती दरों पर पास आज भी जारी किए जाते हैं। लोगों ने रियायती दरों पर पास जारी नहीं करने और दिल्ली मेट्रो के महंगे किराए को भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब देश की राजधानी में उन्हें विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली मेट्रो एक के बाद एक ऐसा फैसला कर रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी शायद यह भूल गए हैं कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उन यात्रियों के प्रति है जो उन्हें महंगा किराया देकर मेट्रो में सफर करते हैं। ये अधिकारी, यह भी भूल जाते हैं कि ये भारत है, जहां नैतिकता से जुड़े मुद्दों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिल्ली मेट्रो ने अब यह फैसला किया है कि वो यात्रियों को अब विज्ञापन सिर्फ दिखाएगा ही नहीं बल्कि सुनाएगा भी। यानी जब आप मेट्रो के अंदर सफर करते समय, यह सुनने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है ताकि आप अपने स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर सकें तो इस बीच आपको दिल्ली मेट्रो अलग-अलग कंपनियों के विज्ञापन सुनने को मजबूर कर देगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने नॉन-ऑपरेशन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ट्रेन के अंदर ऑडियो विज्ञापन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि अधिकारियों ने यह दावा भी किया है कि कंपनियों के ऑडियो विज्ञापन से मेट्रो के अंदर होने वाली जरूरी घोषणाओं जैसे- 'अगला स्टेशन कौन सा है, दरवाजे बंद होने वाले हैं, दरवाजों से हटकर खड़े रहें, यह ट्रेन कहां तक जाएगी' पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, आप खुद ही सोचिए।

विभागों की मलाई पर तकरार-भ्रष्टाचार पर कैसे होगा वार?

- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

वैश्विक स्तरपर आज सारी दुनियाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दंश से अर्थव्यवस्था में कमजोरी महसूस कर रही है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार रूपी काली कमाई भ्रष्टाचारियों द्वारा बेहद सस्पेंस वाली जगह पर छुपा कर रखा जाता है,जो अर्थव्यवस्था के सरकुलेशन में काम नहीं आती। मसलन 2000 के नोटों की लंबी राशि चलन में नहीं आ रही थी यानी मतलब साफ है भ्रष्टाचार्यों के पास लॉक हो गई थी,नतीजा नोटों की नोटबंदी ही पर्याय था। परंतु बहुत ताजुब की बात है एक ओर जहां सरकार भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस करने कमर कसकर भिड़ी हुई है दूसरी ओर हमेशा देखा जाता है की राजनीति में सहयोगी पार्टी या पार्टी के अंदर ही पार्टी के कद्दावर नेताओं में मंत्रालय के विभागों की मलाई पर तकरार होती है, यानें सरकारी टेंडर में परसेंटेज के मामले होते हैं,इसीलिए ही 40 या 50 पेर्सेंट के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में सभी बातें एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं अक्सर चुनाव जीते हुए व्यक्तियों से लेकर मंत्री व चपरासी से लेकर उच्च पदासीन अधिकारी इसमें शामिल होते हैं तो फिर भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति का क्या अर्थ हुआ? जो रेखांकित करने वाली बात है, जिसका सटीक उदाहरण महाराष्ट्र के एक नेता पर गृहमंत्री होने के बावजूद 100 करोड़ प्रतिमाह का आरोप लगा था वो जेल भी गए थे। ऐसे अनेक आरोप राजनीतिज्ञों मंत्रियों पर लगते रहते हैं जो रेखा रेखांकित करने वाली बात है, जिससे क्लियर होता है कि भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे की ओर चलता है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगेविभागों की मलाई पर तकरार, भ्रष्टाचार पर कैसे होगा पलटवार! तथा भ्रष्ट प्लस अचार एट द रेट ऑफ भ्रष्टाचार, लोक निर्माण सरकारी टेंडर गृह परिवहन मंत्रालयों को आखिर क्यों मलाई वाला विभाग कहा जाता है?

साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार के अर्थ को समझने की करें तो, भ्रष्टाचार शब्द दो शब्दों की संधि से बना है - भ्रष्ट +आचार, जिनके निम्न अर्थ हैं-भ्रष्ट= दूषित, गंदा, अनैतिक गलत,आपराधिक, आचार=आचरण, व्यवहार,कार्यकलाप कार्य,तो सीधे शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार का तात्पर्य उस कार्य से है जो गलत हो, अनैतिक हो, आपराधिक हो या दूषित हो।हमारे राजनेताओं की कृपा से आजकल यह शब्द मुख्यतया राजनैतिक संदर्भ में प्रयोग होता है लेकिन सामान्यतया हर वह आचरण भ्रष्टाचार है जो कि किसी गलत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक ढंग से और दुर्भावना से किया जाए।केवल सरकारी कार्यों में घोटाले करना ही भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि अपने आदर्शों से समझौता करना और निजी लाभ के लिए किसी अन्य को पीड़ा पहुंचाना भी भ्रष्टाचार है।दूधवाले का दूध में पानी मिलाना भी भ्रष्टाचार है और शिक्षक का कक्षा में ना पढ़ाना भी भ्रष्टाचार है। अधिकारी का काम ना करना भी भ्रष्टाचार है और काम के बदले रिश्वत मांगना भी भ्रष्टाचार है। टैक्स चोरी करना भी भ्रष्टाचार है और यातायात के नियमों को ना मानना भी भ्रष्टाचार है।सीमित शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार केवल सरकारी योजनाओं में घोटाले करना ही नहीं है बल्कि निजी स्वार्थ सिद्धि हेतु किया गया हर गलत आचरण ही भ्रष्टाचार है। साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार से आर्थिक दुष्प्रभाव की करें तो,भ्रष्टाचार का आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है. मसलन, भ्रष्टाचार के चलते सड़क कमजोर बनायी जाती है, जिससे वह जल्दी टूट जाती है, इस फॉर्मूले के अनुसार भारत और चीन की विकास दर कम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये देश ज्यादा भ्रष्ट हैं,परंतु वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है।भारत और चीन की विकास दर अधिक है।भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि भ्रष्टाचार से प्राप्त रकम का उपयोग किस प्रकार किया जाता है।मान लीजिए एक करोड़ रुपये के सड़क बनाने के ठेके में से 50 लाख रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, सड़क घटिया बनी. प्रश्न उठता है कि घूस की 50 लाख की रकम का उपयोग किस प्रकार हुआ यदि इस रकम को शेयर बाजार में लगाया गया तो भ्रष्टाचार का आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव कुछ घटता है,दक्षिणी अमेरिकी देशों एवं भारत में यह अंतर साफ है। दक्षिण अमेरिका के नेताओं ने घूस की रकम को स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करा दिया। नतीजा विकास में गिरावट आयी,परंतु भारतीय नेताओं ने स्विस बैंकों में जमा कराने के साथ- साथ घरेलू उद्यमियों के पास भी रकम जमा करायी। यदि घूस की रकम का निवेश किया जाये, तो अनैतिक भ्रष्टाचार का आर्थिक सुप्रभाव भी पड़ सकता है।मान लीजिए सरकारी निवेश में औसतन 70 फीसदी रकम का सदुपयोग होता है, जबकि निजी निवेश में 90 फीसदी का, ऐसे में यदि एक करोड़ रुपये को भ्रष्टाचार के माध्यम से निकाल कर निजी कंपनियों में लगा दिया जाये, तो 20 लाख रुपये का निवेश बढ़ेगा।अर्थशास्त्र में एक विधा 'बचत की प्रवृत्ति' के नाम से जानी जाती है। अपनी अतिरिक्त आय में से व्यक्ति कितनी बचत करता है उसे 'बचत की प्रवृत्ति' कहा जाता है। गरीब की 100 रुपये की अतिरिक्त आय हो, तो वह 90 रुपये की खपत करता है और 10 रुपये की बचत. तुलना में अमीर को 100 रुपये की अतिरिक्त आय हो, तो वह 10 रुपये की खपत करता है और 90 रुपये की बचत करता है.मान लीजिए अमीर इंजीनियर ने गरीब किसान से 100 रुपये की घूस ली। गरीब की आय में 100 रुपये की गिरावट आयी, जिसके कारण बचत में 10 रुपये की कटौती हुई. परंतु अमीर इंजीनियर ने 100 की घूस में 90 रुपये की बचत की. इस प्रकार घूस के लेनदेन से कुल बचत में 80 रुपये की वृद्धि हुई।

नकटी ग्राम में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस निम्न स्तरीय राजनीति कर रही है - डॉ. नवीन मार्कण्डेय

कांग्रेस को गरीबों की नहीं, अपने करीबियों की चिंता है – डॉ. नवीन मार्कण्डेय

रायपुर/मूक पत्रिका

कांग्रेस हो चुकी है पीडीएफयाने पर्दा डालो फोर्स

भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नकटी ग्राम में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस अब निम्न स्तरीय राजनीति कर रही है। कांग्रेस नकटी ग्राम के भोले-भाले लोगों को गुमराह करके बरगला रही है, और उन्हें गलत दिशा में ले जाकर आंदोलन कर रही है। डॉ. मार्कण्डेय ने कहा कि यह सारा कृत्य कांग्रेस का किया-धरा है, लेकिन अब कांग्रेस अपनी उस करतूत को भूल नया पाखण्ड रचने में लगी है।भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने आरोप लगाया कि आज नकटी का जो प्रकरण चल रहा है, उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले सन् 2020 में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के शासनकाल में लिखी गई थी। उस समय हाउसिंग बोर्ड के जरिए वहां आवासीय कॉलोनी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमीन मांगे जाने पर। पटवारी, आरआई व तहसीलदार ने चिह्नांकित कर सारी विधिसम्मत प्रक्रिया पूरी कर शासन को सौंपी गई। इसी दरम्यान 2022 में वहां आवासीय कॉलोनी बनने की जानकारी मिलते ही 2022-23 में वहाँ कब्जाधारियों की बाढ़ आ गई। पहले वहां लगभग 3 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था, जिस पर कच्चे मकान चिन्हांकित हुए। डॉ. मार्कण्डेय ने बताया कि नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास के लिए ढाई डिस्मिल जमीन दी जाती है। लेकिन यहां के कई लोगों ने 10 से 17-20 हजार वर्गफीट जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन लोगों ने 50 लाख रुपए मूल्य तक के मकान, बाड़ी बना ली है। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने कहा कि नया राजधानी क्षेत्र के तहत नकटी ग्राम तीसरे लेयर का गांव है और इस लिहाज से उसका चरणबद्ध विकास होना है। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने आवासीय विकास के लिए जगह का चिन्हाकित कर प्रक्रिया पूरी की, उस नजरिए से वहां अतिक्रमण बढ़ा और लोगों ने आवश्यकता से अधिक जमीन पर कब्जा किया। डॉ. मार्कण्डेय ने कहा वि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। गलत दिशा में ले जाकर लोगों को उकसाया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या अवैध कब्जों को वे प्रश्रय देते हैं या देना चाहते हैं? क्या अवैध कब्जा कांग्रेस के लोग पूरे प्रदेश में कराना चाहते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी तो सभी शासकीय भूमि को बेचने के लिए एक नोटिफिक्रेशन जारी किया था, और उस समय कांग्रेस ने बड़े-बड़े नेता तक ने एकड़ों में रियायती दर खरीदें। गरीबों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य प्रयोजन के लिए जो शासकीय जमीन होती है, उसे भी कब्जा करके कांग्रेस शासनकाल में बेचा गया है। बाद में हाईकोर्ट ने इस आदेश को निरस्त किया।भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी एक करतूत को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले समय 122 परिवारों को सेरीखेड़ी में बेघर किया। कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र इतना पतित हो गया है कि उस समय गरीबों को सेरीखेड़ी में हटाया गया, उन गरीबों को न एक इंच जगह तक दी गई और न ही एक कोई मकान दिया। डॉ. मार्कण्डेय ने कहा कि आज घड़ियाली आंसू बहाकर कांग्रेसी प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है कि भाजपा गरीबों के खिलाफ हैं। गरीबों के खिलाफ तो कांग्रेस शुरू से रही है। गरीबी हटाने का नारा देते हुए कांग्रेसी गरीबी नहीं, गरीबों को ही मिटाने का काम करते रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने इस समय पिछले एक साल मे लगातार नकटी ग्राम के बाहर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जाधारियों को नोटिस देते हुए उनके व्यवस्थापन की भी प्रक्रिया की। डॉ. मार्कण्डेय ने कहा कि 29 जून को 61 परिवारों को आवास आबंटित किया और पंजी पर हस्ताक्षर करके ये सब आवास की चाबी लेकर नया रायपुर के सेक्टर-30 में शिफ्ट हुए। इसीलिए शासन-प्रशासन ने कब्जा हटाने की प्रक्रिया की तो उन परिवारों की जरूरत की चीजों तक को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने कहा कि इतनी सब कुछ व्यवस्थित प्रक्रिया कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस प्रदेश में ढाई साल से बैकफुट पर है, किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, जनहित की कोई बात नहीं कर रही है। इसलिए अब झूठे नैरेटिव सेट करके कांग्रेस लोगों को उकसाने के लिए आंदोलन कर रही है। डॉ. मार्कण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार संवेदनशील होकर जन हित में कार्य कर रही है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि कांग्रेस द्वारा यह झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नकटी गांव को तोड़ दिया गया है। श्री श्रीवास ने कहा कि हमारी सरकार ने नकटी गांव को नहीं तोड़ा है। नकटी गांव में कुल 17 वार्ड हैं। उसमें से एक वार्ड, जहां पर कब्जा हुआ था, उनको विस्थापित किया गया है। बार-बार जो यह कहा जा रहा है कि विधायकों के लिए आवास बन रहा है, वह भी सच नहीं है। इन आवासों में अधिकारी-कर्मचारी भी रहेंगे। यह सामूहिक आवास योजना की प्रकिया है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्याम नारंग, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु उपस्थित रहे।

मरेठा से सरगीगुड़ा मुख्य मार्ग बदहाल, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी

बकावंड/मूक पत्रिका

निरमनी बघेल-बकावंड विकासखंड अंतर्गत ग्राम मरेठा से सरगीगुड़ा जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग लंबे समय से बदहाल स्थिति में है। बारिश के मौसम में यह सड़क पूरी तरह कीचड़ और बड़े-बड़े गड्ढों से भर जाती है, जिससे आवागमन अत्यंत कठिन हो गया है। सड़क पर जगह-जगह जलभराव होने के कारण राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर गड्ढे पानी से भर जाने के कारण उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यह मार्ग गांव का मुख्य संपर्क मार्ग है, जिससे प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीणों का आवागमन होता है। इसी रास्ते से छोटे-छोटे स्कूली बच्चे प्रतिदिन विद्यालय पढ़ने जाते हैं। बारिश के दिनों में बच्चों को कीचड़ और पानी से भरे गड्ढों के बीच होकर गुजरना पड़ता है। कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे उन्हें चोट लगने का खतरा बना रहता है। अभिभावकों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण बच्चों को स्कूल भेजना भी चिंता का विषय बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन) लेने के लिए भी उन्हें इसी मार्ग का उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा मरीजों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा दैनिक आवश्यक कार्यों के लिए आने-जाने वाले लोगों को भी इसी सड़क से गुजरना पड़ता है। खराब सड़क के कारण वाहन चालक भी जोखिम उठाकर सफर करने को मजबूर हैं। बरसात के समय कई बार वाहन कीचड़ में फंस जाते हैं, जिससे घंटों तक आवागमन बाधित रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की खराब स्थिति की जानकारी कई बार संबंधित विभाग एवं जनप्रतिनिधियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। सड़क की मरम्मत या पक्कीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण वर्षों से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि मरेठा से सरगीगुड़ा जाने वाले इस मुख्य मार्ग का तत्काल मरम्मत एवं पक्कीकरण कराया जाए, ताकि स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और वाहन चालकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो बरसात के दौरान किसी बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

जिला जेल का कलेक्टर एवं एसएसपी ने किया आकस्मिक निरीक्षण

- जेल में सुरक्षा व्यवस्था एवं बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की ली जानकारी

रायगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह ने शुक्रवार को जिला जेल रायगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में सुरक्षा व्यवस्था एवं बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर गोकुल आर.के., एडीएम अपूर्व प्रियेश टोप्पो, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं एसएसपी ने बंदी बैरकों, जेल अस्पताल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, प्रिजन कॉलिंग सुविधा, बंदी मुलाकात कक्ष तथा पाकशाला का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन एवं बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं प्रत्येक बंदी तक समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पहुंचनी चाहिए। जिला जेल को सुरक्षित, अनुशासित, पारदर्शी और सुधारोन्मुख संस्था के रूप में संचालित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर एवं एसएसपी ने जेल में निरुद्ध बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और सुझावों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित, संवेदनशील एवं नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि बंदियों के अधिकारों और गरिमा का पूर्ण संरक्षण हो सके। निरीक्षण के दौरान बंदी मुलाकात कक्ष में उपस्थित परिजनों से भी अधिकारियों ने चर्चा की। उन्होंने परिजनों से कहा कि यदि किसी भी स्तर पर मारपीट, अवैध धन वसूली अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिले तो उसकी तत्काल शिकायत करें। ताकि दोषियों के विरुद्ध बिना विलंब कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने जेल परिसर तक प्रतिबंधित एवं अवैध सामग्री पहुंचने की संभावित कमजोर कड़ियों की पहचान कर उन्हें तत्काल समाप्त करने तथा निगरानी एवं सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक गोवर्धन सिंह सोरी ने जेल में उपलब्ध व्यवस्थाओं, सुधारात्मक एवं पुनर्वास गतिविधियों तथा बंदियों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।

नारी शक्ति को 'नमस्ते', नए भगवाधारियों को 'सलाम' और अग्रवाल समाज 'आउट': रायगढ़ भाजपा की एल्डरमैन सूची ने फोड़ा बगावत का बम!

रायगढ़/मूक पत्रिका

राजनीति में जब किसी पद के लिए तीन साल तक माथापच्ची चले, तो उम्मीद की जाती है कि परिणाम 'सर्वमान्य' होगा। लेकिन रायगढ़ नगर निगम के लिए भाजपा द्वारा जारी 8 एल्डरमैन की बहुप्रतीक्षित सूची ने पार्टी के भीतर ऐसा राजनीतिक 'रायता' फैला दिया है, जिसे समेटना अब स्थानीय संगठन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। रायगढ़ निगम एल्डर मैंन शुरू से ही संगठन के लिए एक 'सिरदर्द' रहा है, यही वजह है कि यहाँ का नंबर दूसरी लिस्ट में आया। लेकिन लिस्ट आते ही जो बगावत पहले केवल बंद कमरों की कानाफूसी तक सीमित थी, वह अब सोशल मीडिया के चौराहों पर खुल्लम-खुल्ला आ गई है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा रायगढ़ में 'निष्ठावानों' की पार्टी रह गई है, या फिर यह 'आयातित नेताओं' और 'जुगाड़ तंत्र' का नया शरणस्थली बन चुकी है?

वाइट लिस्ट में पांच नाम

सूची में ज्ञानेश्वर गौतम, मनोज शर्मा, मनीष गांधी, प्रदीप श्रृंगी और शशिकांत शर्मा.. ये पांच नाम पहले से ही तय माने जा रहे थे। इनकी निष्ठा, पार्टी के प्रति समर्पण और जमीनी पकड़ पर संगठन में कोई प्रश्नचिह्न नहीं है। ज्ञानेश्वर गौतम और शशिकांत शर्मा जैसे पूर्व मंडल अध्यक्षों का इस सूची में होना उनके राजनीतिक कद के हिसाब से थोड़ा 'हल्का' जरूर है, लेकिन एक समर्पित सिपाही की तरह उन्होंने इसे स्वीकार किया है। वहीं, स्व. भग्गू भाई गांधी के पुत्र मनीष गांधी का दशकों का जमीनी संघर्ष और वर्तमान कार्यालय प्रभार उनके नाम को निर्विवाद बनाता है।

भगवा गमछा, आरएसएस कोटा और 'कांग्रेस' का बैकएंड!

बवाल इन पांच नामों पर नहीं, बल्कि बाकी बचे उन तीन 'विवादित' चेहरों पर है, जिन्होंने रायगढ़ भाजपा की वैचारिक जड़ों पर प्रहार कर दिया है।सुनील थवाईतः युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सूरज शर्मा ने इनका खुलकर विरोध किया है। आरोप बेहद गंभीर हैं! वार्ड चुनावों में कांग्रेस के 'बैकएंड सिपाही' के रूप में काम करना और भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का 'खास' होना। अगर यह सच है, तो भाजपा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पप्पू कुमार (पप्पू पांडे): नया-नया भगवा गमछा ओढ़कर आए पप्पू पांडे के खिलाफ पुराने जमीनी कार्यकर्ताओं ने लिखित शिकायतें तक की थीं। लेकिन संगठन ने पुराने कार्यकर्ताओं के रोष को

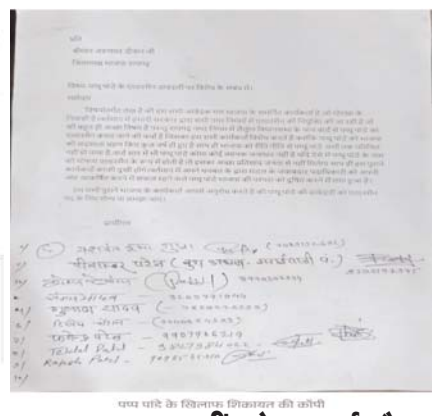

पप्पू पांडे के खिलाफ शिकायत की कॉपी

रद्दी की टोकरी में डाल दिया और पैराशूट से उतरे नेता को कुर्सी सौंप दी।संजय जगवानीः सिंधी समाज के समीकरण के नाम पर जगवानी को एल्डरमैन बनाया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज में इनकी कोई खास पैठ नहीं है। इनकी नियुक्ति शुद्ध रूप से 'आरएसएस कोटा' की उपज मानी जा रही है।

महतारी वंदन' का ढिंढोरा और मातृशक्ति का अपमान

इस सूची का सबसे डार्क और कड़वा पहलू महिलाओं की एकतरफ अनदेखी है। जो पार्टी 33त्न महिला आरक्षण का बिल पास करने पर अपनी पीठ थपथपाती है और 'महतारी वंदन योजना' के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करती है, उसने रायगढ़ में अपनी ही महिला कार्यकर्ताओं का टिकट काट दिया !कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महत्वाकांक्षी महिला नेत्रियों का गुस्सा अब चरम पर है। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अब भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मधुलता पटेल पर भी सीधे तंज कसे जा रहे हैं। दबी जुबान में सवाल उठ रहे हैं कि 'कांग्रेस से आयातित' होने के बावजूद उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिल गई, और वे अपनी ही नेत्रियों का हक क्यों नहीं दिला पाई?

अग्रवाल समाज आउट, 'पावर सेंटर' की हार?

इस पूरी सूची में रायगढ़ के सबसे प्रभावशाली 'अग्रवाल समाज' का पूरी तरह से साफ होना एक बड़े राजनीतिक संदेश की ओर इशारा करता है। ऐश अग्रवाल और बाबूलाल अग्रवाल के नाम पहली लिस्ट में चर्चा में थे। इनकी प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री (ओपी चौधरी) से नजदीकी जगजाहिर है। इसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व द्वारा इनका नाम काटा जाना यह बताता है कि स्थानीय 'पावर सेंटर' की उतनी चली नहीं, या फिर जानबूझकर उन नामों को दरकिनार कर दिया गया।

यह जश्न नहीं, 'रेड अलर्ट' है

फिलहाल लिस्ट आ गई है। मिठाइयां , बधाइयां दी जा रही हैं और साथ ही हर नेता की 'राजनीतिक कुंडली' भी बांची जा रही है। कुछ दिनों में यह शोर शांत भी हो जाएगा। लेकिन संगठन को यह नहीं भूलना चाहिए कि लंबे इंतजार के बाद आई इस लिस्ट ने रायगढ़ भाजपा की नींव में एक ऐसी 'चिंगारी' लगा दी है, जो आने वाले चुनावों में दावानल बन सकती है। दरकिनार किए गए जमीनी कार्यकर्ता और अपमानित मातृशक्ति इस बार फिर खून का घूंट पीकर रह जाएंगे। रायगढ़ भाजपा के लिए यह जश्न का नहीं, बल्कि एक स्पष्ट 'रेड अलर्ट' की शुरुआती चेतावनी है!

तीन वर्षों से अधूरा पड़ा सामुदायिक भवन, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ, जिम्मेदारों की कार्यशैली पर उठे सवाल

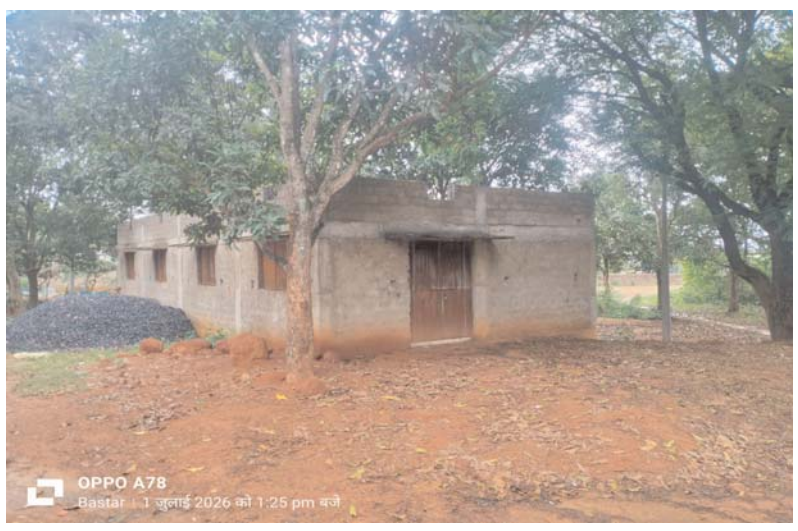

बकावंड/मूक पत्रिका

निरमनी बघेल-विकासखंड बकावंड अंतर्गत ग्राम पंचायत फरसरा में विधायक निधि से स्वीकृत सामुदायिक भवन पिछले लगभग तीन वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। जिस भवन का निर्माण गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के उद्देश्य से कराया जाना था, वह आज भी अधूरी स्थिति में खड़ा है। भवन की दीवारें तो खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण यह ग्रामीणों के किसी भी उपयोग में नहीं आ पा रहा है। भवन के दरवाजे बंद हैं, प्लास्टर एवं अन्य आवश्यक कार्य अधूरे हैं और आसपास का परिसर भी उपेक्षित नजर आता है। धीरे-धीरे यह भवन खंडहर का रूप लेने लगा है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य केवल औपचारिकता निभाने के लिए शुरू किया गया था और बाद में उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सामुदायिक भवन बनने से गांव में विवाह, बैठक, ग्राम सभा, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम, महिला समूहों की बैठक, युवाओं के कार्यक्रम तथा शासकीय योजनाओं से संबंधित बैठकों के आयोजन के लिए एक स्थायी स्थान उपलब्ध हो जाता। लेकिन तीन वर्षों से भवन अधूरा पड़े रहने के कारण ग्रामीणों को आज भी खुले मैदान, स्कूल परिसर या निजी स्थानों का सहारा लेना पड़ता है। बरसात और गर्मी के मौसम में कार्यक्रम आयोजित करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य शुरू होने के कुछ समय बाद ही काम पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके बाद न तो किसी अधिकारी ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और न ही इसे दोबारा शुरू कराने की कोई गंभीर पहल की गई। कई बार ग्रामीणों द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिलता रहा। वर्षों बीत जाने के बावजूद भवन आज भी अधूरा पड़ा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए लाखों रुपये स्वीकृत किए जाते हैं ताकि गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो सके। लेकिन यदि निर्माण कार्य समय पर पूरे नहीं होंगे तो ऐसी योजनाओं का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अधूरा भवन न केवल सरकारी धन की बर्बादी का उदाहरण बन रहा है, बल्कि विकास कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच एवं सचिव की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य को पूरा कराने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई गई। यदि पंचायत स्तर पर समय-समय पर निर्माण कार्य की समीक्षा की जाती और संबंधित एजेंसी पर दबाव बनाया जाता, तो भवन काफी पहले बनकर तैयार हो जाता। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरा भवन गांव की विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर कर रहा है। बारिश और मौसम की मार के कारण भवन की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दीवारों में सीलन आने लगी है और लंबे समय तक निर्माण अधूरा रहने से भवन की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ गई है। यदि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया तो भविष्य में भवन की मरम्मत पर अतिरिक्त सरकारी राशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान होगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिला प्रशासन, जनपद पंचायत बकावंड तथा संबंधित विभाग इस मामले की निष्पक्ष जांच कर यह पता लगाए कि आखिर तीन वर्षों से निर्माण कार्य क्यों बंद पड़ा है। निर्माण कार्य में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों तथा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही भवन के शेष कार्य को शीघ्र पूरा कर ग्रामीणों के उपयोग के लिए सौंपा जाए, ताकि शासन की इस जनहितकारी योजना का वास्तविक लाभ गांव के लोगों को मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन यदि जिम्मेदार अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेंगे तो ऐसी योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। फरसरा का अधूरा सामुदायिक भवन इसी लापरवाही की एक बड़ी मिसाल बन गया है। अब ग्रामीणों की नजर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस अधूरे भवन का निर्माण पूरा कर गांव को उसकी बहुप्रतीक्षित सौगात मिलेगी।

बदहाली की मार झेल रहा मलांजकुंडुम जलप्रपात, सुविधाओं के अभाव से लौट रहे पर्यटक

जिला मुख्यालय से महज 20 किमी दूर स्थित प्राकृतिक धरोहर की सुध लेने की मांग, स्थानीयों ने कहा-विकास होगा तो बढ़ेगा रोजगार

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/कांकेर:-कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की मनोरम वादियों के बीच स्थित मलांजकुंडुम जलप्रपात इन दिनों शासन-प्रशासन की अनदेखी के चलते बदहाली का शिकार बना हुआ है। बरसात के मौसम में दूधनदी का कल-कल करता जल इस जलप्रपात की सुंदरता में चार चांद लगा देता है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से इस पर्यटन स्थल के विकास और सौंदर्गीकरण की बातें होती रही हैं, लेकिन धरातल पर अब तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। न तो पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं और न ही सुरक्षा व स्वच्छता की समुचित व्यवस्था की गई है। इसका असर यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या पर भी दिखाई देने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय स्तर पर ग्राम समिति बनाकर साफ-सफाई और व्यवस्थाएं बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाले पर्यटकों को परेशानी न हो। बावजूद इसके, बड़े स्तर पर विकास कार्यों के लिए शासन-प्रशासन की पहल जरूरी है। उनका कहना है कि अधिकारी स्थल का निरीक्षण तो करते हैं और विकास के आश्वासन भी देते हैं, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नजर नहीं आती।

स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि मलांजकुंडुम जलप्रपात का सुनियोजित विकास किया जाए, तो यह क्षेत्र प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि आसपास के ग्रामीणों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि इस प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करते हुए आवश्यक पर्यटन सुविधाएं शीघ्र विकसित की जाएं, ताकि मलांजकुंडुम जलप्रपात अपनी पहचान के अनुरूप पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान प्राप्त कर सके।

वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए वन अमले को मिला प्रशिक्षण

95 अधिकारी-कर्मचारियों को कानून, साक्ष्य संकलन और न्यायालयीन प्रक्रिया की दी जानकारी

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। वन्यजीव संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वनमंडल बीजापुर में शुक्रवार को एक दिवसीय वनमंडल स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डीएफओ डॉ. जाधव सागर रामचंद्र के मार्गदर्शन में हुए प्रशिक्षण में वन विभाग के 95 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में बांधवगढ़ (मध्यप्रदेश) से आए विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र मिश्रा एवं अधिवक्ता यश कुमार सोनी ने वन्यजीव अपराधों की रोकथाम, साक्ष्य संकलन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 2022), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा न्यायालयीन प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण का उद्देश्य मैदानी अमले को कानूनी प्रावधानों से अवगत कराते हुए वन्यजीव अपराधों में प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत परिवाद प्रस्तुत करने के लिए तैयार करना रहा।कार्यक्रम में वनमंडल के सभी उपवनमंडलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, उपवनक्षेत्रपाल, वनपाल एवं वन रक्षक उपस्थित रहे। प्रशिक्षकों ने वन्यजीव अपराधों की जांच और अभियोजन से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर भी मार्गदर्शन दिया।इस दौरान एसडीओ देवेंद्र गोंड ने वर्षा ऋतु के मद्देनजर मैदानी अमले को नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जंगलों में अवैध साफ-सफाई, अतिक्रमण और वृक्षों की अवैध कटाई जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर नियमानुसार वन अपराध दर्ज कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

शत-प्रतिशत उपस्थिति के लिए शिक्षिका ममता जायसवाल ने चलाया डोर-टू-डोर पालक सम्पर्क अभियान

चांपा/मूक पत्रिका

शासकीय प्राथमिक शाला सोंठी में छात्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षिका ममता जायसवाल के द्वारा डोर-टू-डोर पालक सम्पर्क अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षिका ममता विगत एक सप्ताह से प्रतिदिन शाला की छुट्टी के बाद ग्राम के विभिन्न मोहल्लों में जाकर पालकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर रही हैं। इस दौरान बच्चों की नियमित उपस्थिति, पढ़ाई और आगामी समर कैंप में भागीदारी को लेकर पालकों से विस्तार से चर्चा की जा रही है। जो बच्चे लगातार अनुपस्थित रहते हैं, उनके घर जाकर अनुपस्थिति का कारण जाना जा रहा है। साथ ही पालकों को शिक्षा के महत्व और नियमित स्कूल आने के फायदे बताए जा रहे हैं। कई पालकों को स्कूल में आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी दी जा रही है। ममता जायसवाल ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

घर-घर जाकर संवाद करने से पालकों का सहयोग मिल रहा है और इसका सकारात्मक असर उपस्थिति पर दिखने लगा है। इस पहल की सराहना शाला प्रबंधन समिति, ग्राम के सरपंच और स्थानीय पालकों द्वारा की जा रही है। अभियान के बाद शाला की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा मददेड़, 8 जुलाई को होगी शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा

5 से 11 जुलाई तक सात दिवसीय धार्मिक महोत्सव, कलश यात्रा से महायज्ञ तक होंगे विविध आयोजन

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। जिले के मददेड़ गांव में नव निर्मित श्री शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं कलश स्थापना महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पूरे गांव में इन दिनों शिवभक्ति का माहौल है। मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट, विद्युत रोशनी और भगवा ध्वजों से सजाया गया है, जबकि ÷हर-हर महादेव÷ और ÷?

नमः शिवाय÷ के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। श्री सीताराम शिवालय समिति एवं ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वावधान में 5 से 11 जुलाई तक सात दिवसीय धार्मिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 5 जुलाई को वरुण पूजन, गौरी-गणेश पूजन, घट स्थापना, भगवान शिव की नगर भ्रमण शोभायात्रा और कलश यात्रा के साथ आयोजन का शुभारंभ होगा। इसके बाद प्रतिदिन वैदिक परंपरा के अनुसार विभिन्न अधिवास, पूजन एवं आरती के कार्यक्रम होंगे।

महोत्सव का मुख्य आकर्षण 8 जुलाई को रहेगा। ब्रह्ममुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। इसके बाद रुद्राभिषेक, महाआरती और विशेष पूजा-अर्चना होगी। आयोजन में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।9 जुलाई को मंदिर के शिखर एवं ध्वज की स्थापना, 10 जुलाई को महायज्ञ, पूर्णाहुति और विशाल महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। 11 जुलाई को शिव नामकरण विधि एवं आचार्य प्रस्थान के साथ महोत्सव का समापन होगा। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से परिवार सहित आयोजन में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि यह आयोजन केवल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आस्था, सामाजिक एकता और सनातन संस्कृति का उत्सव है। मददेड़ गांव भगवान भोलेनाथ के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है।

बीरगांव नगर निगम की बड़ी उपलब्धि, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आवास दिलाने में बीरगाँव रहा छत्तीसगढ़ में अव्वल

300+ गरीब परिवारों के पक्के आवास बनकर तैयार, जल्द होगा गृह प्रवेश

रायपुर (बीरगांव)/मूक पत्रिका

(अंकित तिवारी) । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में शहरी निर्धन परिवारों को स्वयं का आवास उपलब्ध करने की जो पहल छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है उसमे बीरगांव नगर निगम में सर्वाधिक 300+ परिवारों को आवास प्रदान कर राज्य के नगरीय निकायों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती आर. संगीता के सतत निर्देशन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 'मोर जमीनङ्कमोर मकान' (क्ख्रठ्ठदृद्वद्वष्ड्डुह्ल4 स्न्नस्र ष्टश्ठ्ठद्यह्लद्धद्धष्ह्लद्वश्ठ्ठ-क्चष्ट) घटक के तहत 300 हितग्राहियों के पक्के आवासों का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। नगर पालिक निगम बीरगांव के आयुक्त श्री युगल किशोर उर्वशा ने इस उपलब्धि के लिए उप मुख्यमंत्री श्री साव व विभागीय सचिव के सतत मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताते हुए निगम के अधिकारी कर्मचारियों एवं मैदानी अमले की सराहना की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया, जिनके पास स्वयं का भूखंड उपलब्ध था। शासन द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता एवं निगम प्रशासन की सतत मॉनिटरिंग, तकनीकी मार्गदर्शन तथा समयबद्ध क्रियान्वयन व निरंतर जागरूकता कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 300+ परिवारों के सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आवास तैयार हो चुके हैं। इन हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी अतिशीघ्र एक गरिमामय समारोह में होगा ।आयुक्त श्री उर्वशा ने आगे बताया कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्माण चरण की जियो-टैगिंग की गई। निर्माण प्रगति के सत्यापन के उपरांत हितग्राहियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से समय पर किस्तों की राशि हस्तांतरित की गई। समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध होने से हितग्राहियों ने निर्धारित अवधि में अपने आवासों का निर्माण पूर्ण किया। उल्लेखनीय है की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विजन तथा उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के निर्देशन में प्रदेश में शहरी गरीबों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। विभाग की सचिव श्रीमती आर. संगीता के मार्गदर्शन में योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।आयुक्त श्री उर्वशा ने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि यह उपलब्धि न केवल गरीब एवं आवासहीन परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ और समावेशी शहरी विकास की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को भी सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करेगी।

बरसात में खुद नाली में उतरे पार्षद विकास तम्बोली, पांच घंटे तक की सफाई

बेमेतरा/मूक पत्रिका

मानसून की पहली तेज बारिश के बाद वार्ड क्रमांक 11 में जलभराव की स्थिति बन गई। कई गलियों और मोहल्लों में नालियों का पानी भरने लगा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद एवं नगर पालिका सभापति विकास तम्बोली स्वयं सफाई अभियान में जुट गए। बताया गया कि विकास तम्बोली ने पंजाबी पारा, गंजपारा, दुर्ग रोड, गस्ती चौक, आरामिल गली, रायपुर रोड तथा मंडी से लगी बड़ी नाली सहित पूरे वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं नाली में जमा मलवा निकालकर सफाई की, जिससे छोटी नालियों का पानी बड़ी नाली के माध्यम से बाहर निकल सका। उन्होंने करीब पांच घंटे तक बारिश में भीगते हुए सफाई कार्य किया।विकास तम्बोली ने कहा कि वार्ड में बरसात से पहले बड़ी नालियों की सफाई कराने के लिए नगर पालिका से कई बार आग्रह किया गया था, लेकिन समय पर कार्य नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई। उनका कहना है कि यदि पूर्व में नियमित रूप से नालियों की सफाई कराई जाती, तो लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।उन्होंने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले वर्षों की तरह इस बार सभी वार्डों में समय रहते नालियों की सफाई नहीं कराई गई। इससे कई वार्डों में जलभराव की समस्या सामने आई।पार्षद विकास तम्बोली ने वार्डवासियों एवं नगरवासियों से अपील की कि घरों का कचरा नालियों या सड़कों पर न फेंकें। उन्होंने कहा कि सूखा और गीला कचरा नगर पालिका की ई-रिक्शा के माध्यम से ही दें, ताकि नालियां जाम न हों और भविष्य में इस तरह की समस्या से बचा जा सके।

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने गिरोला स्थित मां हिंगलाजिन मंदिर में किए दर्शन, प्रदेश एवं बस्तर की सुख-समृद्धि की कामना

गिरोला/मूक पत्रिका

बकावंड/मूक पत्रिका निरमनी बघेल। दिनांक 03 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत अपने बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर विधायक श्री लखेश्वर बघेल के साथ बकावंड विकासखंड अंतर्गत गिरोला स्थित प्रसिद्ध मां हिंगलाजिन मैया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उनके साथ क्षेत्र के विधायकगण, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि, ब्लॉक अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंदिर पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पमालाओं से आत्मीय स्वागत किया गया। मंदिर के मुख्य पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक धार्मिक विधि-विधान के साथ विशेष पूजा-अर्चना संपन्न कराई। नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत एवं बस्तर विधायक श्री लखेश्वर बघेल ने मां हिंगलाजिन के चरणों में प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति, खुशहाली तथा बस्तर अंचल के निरंतर विकास की कामना की। उन्होंने किसानों की समृद्धि, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, महिलाओं के सम्मान एवं समाज में आपसी भाईचारे की भावना बनाए रखने की भी प्रार्थना की। पूजा-अर्चना के पश्चात श्री चरणदास महंत ने उपस्थित लोगों से आत्मीय मुलाकात की तथा मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल हमारी संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। ऐसे पावन स्थलों पर आकर मन को शांति मिलती है और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने मां हिंगलाजिन से प्रदेश में शांति, समृद्धि और विकास की निरंतर प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर बस्तर विधायक श्री लखेश्वर बघेल ने कहा कि मां हिंगलाजिन माँ के प्रति क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था है और यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने क्षेत्र के विकास, जनकल्याण और सामाजिक सौहार्द के लिए निरंतर कार्य करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। कार्यक्रम में उपस्थित विधायकगण, जिला अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी मां हिंगलाजिन के दर्शन कर प्रदेश एवं क्षेत्र की उन्नति और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में पूरे समय श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं द्वारा मां हिंगलाजिन के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा।दर्शन-पूजन के उपरांत सभी जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना तथा क्षेत्र के विकास कार्यो पर चर्चा की। ग्रामीणों ने भी अपने बीच प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया।धार्मिक आस्था, सामाजिक सौहार्द और जनसंपर्क से परिपूर्ण यह कार्यक्रम क्षेत्र के लिए विशेष महत्व का रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमामय बना दिया। मां हिंगलाजिन के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ यह धार्मिक आयोजन प्रदेश एवं बस्तर अंचल की सुख-समृद्धि, शांति और सर्वांगीण विकास की मंगलकामनाओं के साथ संपन्न हुआ।

संक्षिप्त समाचार

अरब सागर में उतरा अमेरिकी हेलीकॉप्टर: घटना में एक क्रू सदस्य लापता, तलाश जारी

मनामा, एजेंसी। अमेरिकी नौसेना के एक हेलीकॉप्टर को अरब सागर में इमरजेंसी वॉटर लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी 5वीं फ्लीट ने जानकारी दी है कि विमानवाहक पोत 'यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश' से जुड़े एक 'एमएच-60एस सी हॉक' हेलीकॉप्टर को पानी में उतरना पड़ा। यह घटना 1 जुलाई को सुबह करीब 3 :30 बजे हुई। नौसेना ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर में कुल चार क्रू मेंबर सवार थे। इमरजेंसी वॉटर लैंडिंग के बाद तीन सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्हें इलाज के लिए विमानवाहक पोत पर ले जाया गया है और उनकी हालत अब स्थिर है। हालांकि, चौथा सदस्य अब भी लापता है। अमेरिकी नौसेना के जहाज और अन्य संसाधन इलाके में लापता सदस्य को ढूंढने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस इमरजेंसी वॉटर लैंडिंग के पीछे किसी दुश्मन के हमले या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का कोई संकेत नहीं मिला है। नौसेना ने स्पष्ट किया है कि इस घटना के असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पूरा ध्यान लापता सदस्य को सुरक्षित ढूंढने पर है। इमरजेंसी वॉटर लैंडिंग जिसे डिचिंग भी कहा जाता है, वह स्थिति होती है जब किसी विमान को तकनीकी खराबी, इंजन फेल होने, ईंधन खत्म होने या अन्य गंभीर आपात स्थिति के कारण पानी (समुद्र, नदी या झील) पर उतारना पड़ता है, जबकि उसकी सामान्य लैंडिंग किसी हवाई अड्डे पर संभव नहीं होती। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। नॉर्थ डकोटा रवाना होने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने (डीन्यूक्लियराइजेशन) की प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है। ट्रंप इस कूटनीतिक प्रक्रिया को लेकर काफी उत्साहित दिखे। ट्रंप ने बताया कि पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान पर तीन रातों तक कड़े हमले किए थे। ये हमले उन जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में थे, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे थे। ट्रंप का दावा है कि इन हमलों के बाद ईरान के रुख में काफी बदलाव आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप का मानना है कि हालिया सैन्य दबाव ने ईरान को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर किया है। हालांकि, कतर में चल रही उच्च स्तरीय बातचीत में ईरान सीधे तौर पर शामिल नहीं है, फिर भी ट्रंप ने बातचीत में प्रगति होने की बात कही है।

ट्रंप बोले- जन्मसिद्ध नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट गलत था, लेकिन यह मामला सुलझ जाएगा

नॉर्थ डकोटा, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर एक बार फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मामले में गलत फैसला दिया, लेकिन उन्हें भरोसा है कि भविष्य में यह मुद्दा सुलझ जाएगा। ट्रंप ने यह बयान नॉर्थ डकोटा के मेडोरा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में दिया। ट्रंप ने कहा कि जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रावधान मूल रूप से गृहयुद्ध के बाद गुलामों के बच्चों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया था। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य दूसरे देशों के संपन्न लोगों के बच्चों को स्वत: अमेरिकी नागरिकता देना नहीं था। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता, बल्कि मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गलत था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसका समाधान कर लेंगे।' राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाने वाले फैसले की सराहना ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी स्वागत किया, जिसमें राष्ट्रपति को कार्यपालिका की एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने के अधिक अधिकार मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने लगभग 90 साल पुराने कानूनी ढांचे को बदलते हुए राष्ट्रपति पद की शक्तियां बहाल की हैं। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला 6-3 के बहुमत से आया और यह राष्ट्रपति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, ऐसे समय में जब राष्ट्रपति को अधिक अधिकारों की जरूरत है, यह फैसला बहुत अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में दाखिले और अवसर योग्यता के आधार पर मिलेंगे, न कि किसी व्यक्ति की नस्ल या पहचान के आधार पर। उन्होंने कहा कि पहले कई बार कम अंक पाने वाले छात्रों को उनकी पहचान के आधार पर प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश मिल जाता था।

यूरोप में साइलेंट किलर से घर बने ओवन; स्पेन में 1000 से अधिक मौतें, हंगरी और स्लोवाकिया में भी तापमान के टूटे रिकॉर्ड

पेरिस, लंदन, एजेंसी। यूरोप इस समय वर्षों की सबसे भीषण गर्मी झेल रहा है। फ्रांस, स्पेन, हंगरी, स्लोवाकिया, इटली, पुर्तगाल और बाल्कन देशों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। कई देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है, जल संकट गहरा गया है और सरकारों को आपात कदम उठाने पड़ रहे हैं।स्लोवाकिया के कामेनिका नाद ह्रोनोम में तापमान 41.3एष्ट दर्ज किया गया, जो देश का अब तक का सर्वाधिक तापमान है। हंगरी के सेचेनी में पारा 42एष्ट तक पहुंच गया, जिसने 2007 का 41.9एष्ट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन रिकॉर्डों ने पूरे मध्य यूरोप में भीषण गर्मी की गंभीरता को उजागर कर दिया है। स्पेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार जून महीने में 1,000 से अधिक लोगों की मौत गर्मी से जुड़ी वजहों से हुई। यह पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है। वहीं, 2026 का पहला छह महीनों का दौर स्पेन के इतिहास का सबसे गर्म पहला

अर्धवार्षिक काल दर्ज किया गया। फ्रांस में अस्पताल हाई अलर्ट पर फ्रांस में जून के दौरान तापमान 40.9एष्ट तक पहुंच गया। गर्मी से मौतों की संख्या बढ़ने के बाद अस्पतालों को अगली हीटवेव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।अस्पतालों में ठंडे पानी के स्नान की व्यवस्था की जा रही है। अतिरिक्त कूलिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। बुजुर्गों और गंभीर मरीजों की विशेष निगरानी की जा रही है। पुर्तगाल के मौसम विभाग ने लिस्बन, सेतुबाल, लेइरिया और कोइम्ब्रा क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में तापमान 44एष्ट तक पहुंचने की आशंका है। पेरिस के 21 वर्षीय छात्र यूलिस ज़ाकरी ने बताया कि उनका छोटा कमरा कुछ घंटों की धूप के बाद इतना गर्म हो जाता है कि वहां रहना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका और जापान के लगभग 90त्न घरों में एयर कंडीशनर हैं। यूरोप में यह आंकड़ा केवल करीब 25त्न है। इसका कारण यह है कि यूरोप के अधिकांश घर ठंड से बचाव के लिए बनाए गए थे। मोटी दीवारें और अधिक इंसुलेशन सर्दियों में तो लाभदायक हैं, लेकिन अब वही घर गर्मियों में गर्मी को भीतर फंसा देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अत्यधिक गर्मी को साइलेंट किलर बताया है। संगठन का कहना है कि मौजूदा हीटवेव भविष्य की और भी गर्म गर्मियों की एक चेतावनी है और यूरोप को अपने शहरों, स्वास्थ्य व्यवस्था और भवन निर्माण की नीति में बड़े बदलाव करने होंगे।

ईरान ने आईएईए को परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने से किया इनकार, गालिबाफ बोले- कानून इसकी अनुमति नहीं देता

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हाल में हमले का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षकों को अनुमति नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि इन ठिकानों तक आईएईए की पहुंच की खबरें पूरी तरह गलत हैं और देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सरकारी टीवी चैनल आईआरआईबी को दिए साक्षात्कार में गालिबाफ ने कहा कि ईरानी संसद और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐसा कानून बनाया है, जिसके तहत बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों तक किसी भी परिस्थिति में विदेशी निरीक्षकों को पहुंच नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि निरीक्षकों को वही पहुंच मिलेगी, जिसकी अनुमति सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देगी। गालिबाफ ने स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता में अपनी भागीदारी का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि इन वार्ताओं से ईरान की कुछ संपत्तियों की रिहाई की प्रक्रिया तेज हुई और कुछ प्रतिबंधों को निलंबित करने की दिशा में प्रगति हुई। उनके अनुसार, यदि ईरान बातचीत में शामिल नहीं होता तो समझौते की शर्तों को आगे बढ़ाना संभव नहीं होता। ईरानी संसद अध्यक्ष ने कहा कि देश को कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मन केवल ताकत की भाषा समझते हैं, इसलिए देश को मजबूत रहना होगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए आलोचकों से कहा कि वे ट्रंप की भाषा न दोहराएं और देश की जनता को शांति से रहने दें। गालिबाफ ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी सभी ईरानियों की सेवा करना है, चाहे उनका धर्म या विचार कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आर्थिक समस्याओं का समाधान, देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है।

रूस के हमले से दहली यूक्रेन की राजधानी: कीव में रात भर मिसाइल-ड्रोन की गर्जना से सहमे लोग; आठ लोगों की हुई मौत

कीव, एजेंसी। रूस ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया। इसके कारण भीषण विस्फोट हुए और कीव कई घंटों तक हिलता रहा। कीव शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख तैमूर टकाचेंको ने बताया कि हमलों में आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनमें आठ लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं।

कितने जिलें प्रभावित हुए?: बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों तथा ड्रोन से हुए हमले ने नीप्रो नदी के दोनों किनारों पर स्थित शहर के सभी 10 जिलों को प्रभावित किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की और अन्य अधिकारियों द्वारा हमले की पहली चेतावनी जारी किए जाने के बाद कई निवासियों ने मेट्रो स्टेशनों पर शरण ली।

क्लिट्स्को ने निवासियों ने क्या आग्रह किया: रूस ने हाल के हफ्तों में कीव पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं, यूक्रेन द्वारा रूसी सैन्य स्थलों और ऊर्जा सुविधाओं के खिलाफ किए गए लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के कारण रूस के अंदर ईंधन की कमी हो गई है। इसके साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो गई हैं। क्लिट्स्को ने निवासियों से आश्रय स्थलों में रहने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि शेवचेनकिस्की जिले में पांच लोग घायल हुए हैं और घायलों में से एक, जो एक पैरामेडिक है, उसकी हालत बेहद गंभीर है। क्लित्स्को ने बताया कि देसनियांस्की जिले में एक क्षतिग्रस्त नौ मंजिला आवासीय इमारत में लोग फंसे हुए थे और बचाव दल घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। वहीं, होलोसिवस्की जिले में एक बहुमंजिला इमारत की छत पर आग लग गई। स्विआतोशिन्स्की और डार्नीत्स्की जिलों में घरों में आग लग गई।

अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे

कीव शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमुर टकाचेंको ने बताया कि हमले में देसनियांस्की जिले में एक आवासीय इमारत आंशिक रूप से नष्ट हो गई, पेचेर्स्की जिले में दो स्थानों पर आवासीय इमारतों के पास आग लग गई और सोलोमियांस्की जिले में एक प्रशासनिक भवन के पास आग लग गई। उन्होंने कहा कि अधिकारी ओबोलोंस्की और पोडिल्स्की जिलों में भी नुकसान का आकलन कर रहे हैं।

वेनेजुएला में भारतीय सेना का राहत मिशन युद्धस्तर पर जारी, मलबे से 79 वर्षीय महिला को बचाया

काराकस, एजेंसी। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप बाद भारतीय सेना ने मलबे के नीचे फंसी एक 79 साल की बुजुर्ग महिला को सफलतापूर्वक निकाला। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय मिशन के हिस्से के तौर पर उसका इलाज शुरू किया गया। भारतीय आर्मी ने समय रहते महिला को बाहर निकालकर उन्हें तुरंत फील्ड अस्पताल में पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच सकी। भारतीय सेना के इस काम की वेनेजुएला में हर जगह तारीफ हो रही है। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वेनेजुएला के उन परिवारों के वीडियो शेयर किए जो आर्मी फील्ड हॉस्पिटल में देखभाल के लिए भारत का धन्यवाद कर रहे थे। अभी महिला का नाम पता नहीं चला है लेकिन भारतीय सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए तेजी से काम कर रही है और मानवीय सहायता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहरा रही है।

महिला के पैर में फ्रैक्चर था, साथ ही पेरिफेरल आर्टरी की बीमारी भी थी। मलबे के नीचे फंसने के कारण इलाज में देरी भी उनकी जान ले सकती थी, क्योंकि गंभीर आर्टरी अल्सर और तेज दर्द बढ़ गया था। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह वेनेजुएला में भूकंप पीड़ितों के साथ हरसंभव मदद को तैयार है। भारतीय सेना ने इस बुजुर्ग महिला को तुरंत संभाला और फ्रैक्चर का इलाज किया। वहीं घावों को भी देखभाल भी की गई, जिससे उनके मन में तुरंत ठीक होने की उम्मीद जागी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, वेनेजुएला के लोगों के साथ भारत एकजुट है। पिछले हफ्ते वेनेजुएला में आए दो जबरदस्त भूकंपों में 2200 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद बचाव और राहत का काम जारी है।

कतर की मध्यस्थता रंग लाई: दोहा में यूएस-ईरान वार्ता से बढ़ी उम्मीद, 14 सूत्रीय समझौते पर हुई सकारात्मक चर्चा

दोहा, एजेंसी। कतर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार कतर और पाकिस्तान ने दोहा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के साथ अलग-अलग बैठकें संपन्न कीं। जिनमें 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। गुरुवार को एक एक्स पोस्ट में कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता माजेद अल अंसारी ने कहा कि वार्ता लेक ल्यूसर्न शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आधारित थी। यह ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम यात्रा के बाद जारी रहेगी। तसनीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम रारीबाबादी ने कहा 'हमने दोहा बैठक में लेबनान में

प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अमेरिका की विफलता का मुद्दा उठाया था।' उन्होंने आगे कहा कि कतर के अधिकारियों के साथ बैठकों में 6 अरब अमेरिकी डॉलर के एक हिस्से के खर्च से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही इस बैठक में यह सहमति हुई कि घोषित जरूरतों के आधार पर, आवश्यक वस्तुओं की खरीद की जाएगी। उन्हें ईरान के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अंतिम यात्रा 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के अलग- अलग स्थानों पर करने की योजना हैं। बता दें कि खामेनेई की मृत्यु 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका-इस्राइल युद्ध के पहले दिन एक हवाई हमले में हुई थी। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अच्छी तरह चल रहा है। कतर में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की भागीदारी वाली उच्च स्तरीय वार्ता से ईरान की अनुपस्थिति के बावजूद इस्लामिक गणराज्य के साथ राजनयिक प्रक्रिया के बारे में आशावाद व्यक्त किया था। नवनिर्मित थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का दौरा करने के लिए नॉर्थ डकोटा रवाना होते समय पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमलों के जवाब में इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ हाल ही में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी है।

भारत के 100 रुपए उज़्बेकिस्तान में बन जाते हैं 13,000 से ज्यादा

ताशकंद, एजेंसी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां भारत के सिर्फ 100 रुपये के बदले करीब 13,000 से 15,000 तक मिल सकते हैं। जी हां, यह देश न तो वियतनाम है, न इंडोनेशिया दरअसल यह उज़्बेकिस्तान है, जो इन दिनों भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि, हजारों की संख्या में स्थानीय मुद्रा मिलने का मतलब यह नहीं है कि भारतीय रुपया वहां बेहद मजबूत है। इसके पीछे की असली वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

उज़्बेकिस्तान की मुद्रा उज़्बेक सोम है। मौजूदा विनिमय दर के अनुसार, 100 भारतीय रुपये के बदले लगभग 13,000 से 15,000 उज़्बेक सोम मिल सकते हैं। पहली नजर में यह आंकड़ा काफी बड़ा लगता है और ऐसा महसूस हो सकता है कि भारतीय रुपया वहां बहुत ज्यादा मजबूत है। हालांकि, इसकी असली वजह कुछ और है। उज़्बेकिस्तान की मुद्रा की एक यूनिट की कीमत भारतीय रुपये की तुलना में काफी कम है। इसी कारण कम भारतीय रुपये भी हजारों उज़्बेक सोम में बदल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय रुपये की खरीदने की क्षमता बहुत अधिक है, बल्कि यह वहां की मुद्रा के मूल्य को दर्शाता है। समय-समय पर बदलती रहती है, इसलिए मिलने वाली राशि में भी बदलाव संभव है।

भारतीय पर्यटकों के बीच बढ़ रही है उज़्बेकिस्तान की लोकप्रियता: पिछले कुछ सालों में उज़्बेकिस्तान भारतीय यात्रियों की पसंदीदा विदेशी जगहों में शामिल हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहां का कम यात्रा खर्च और ऐतिहासिक विरासत है।

यहां होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट और भोजन का खर्च कई यूरोपीय और पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम माना जाता है। यही कारण है कि कम

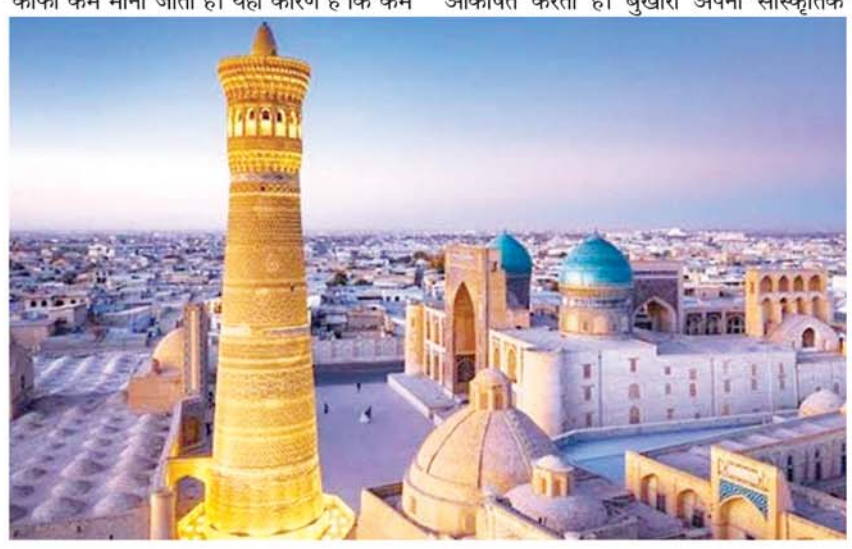

बजट में विदेश घूमने की योजना बनाने वाले लोग इस देश को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा, उज़्बेकिस्तान अपनी सिल्क रोड की ऐतिहासिक विरासत, शानदार मस्जिदों, नीले गुंबदों वाले स्मारकों और पारंपरिक मध्य एशियाई व्यंजनों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

उज़्बेकिस्तान में घूमने की प्रमुख जगहें: समरकंद: समरकंद उज़्बेकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल शहर माना जाता है। यहां स्थितरेगिस्तान स्क्वायर दुनिया की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है। शानदार इस्लामी वास्तुकला, प्राचीन मदरसे और ऐतिहासिक इमारतें यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। बुखारा अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है। यहां सदियों पुराने मदरसे, ऐतिहासिक मस्जिदें और पारंपरिक बाजार आज भी अपनी पुरानी पहचान बनाए हुए हैं। यह शहर इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले यात्रियों के लिए खास आकर्षण है। देश की राजधानी ताशकंद आधुनिक सुविधाओं और ऐतिहासिक धरोहर का शानदार मेल है। यहां चौड़ी सड़कें, आधुनिक इमारतें, संग्रहालय, पार्क और सांस्कृतिक स्थल पर्यटकों को अलग अनुभव देते हैं।

चीन में 200 रूसी सैनिकों की सीक्रेट ट्रेनिंग; पुतिन के करीबी ने दी मंजूरी

बीजिंग, मास्को, एजेंसी। रूस और चीन के बढ़ते रक्षा सहयोग को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गोपनीय रूसी दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि वर्ष 2025 में करीब 200 रूसी सैनिकों ने चीन में विशेष सैन्य प्रशिक्षण लिया। हालांकि, चीन ने इस दावे को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है, जबकि रूस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव ने एक आंतरिक आदेश जारी कर रूसी सैन्य प्रतिनिधिमंडल को चीन भेजने की मंजूरी दी थी। बताया गया है कि प्रशिक्षण लगभग तीन सप्ताह तक चला और इसमें कम से कम चार रूसी और चीनी जनरल भी शामिल थे। यह प्रशिक्षण चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सैन्य सुविधाओं में आयोजित किया गया। रॉयटर्स के मुताबिक, इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल सुरक्षा था। रूसी सैनिकों को परमाणु, रासायनिक और जैविक हमलों से बचाव, रेडिएशन और केमिकल रिकॉनिसेंस तथा वेंटिलेशन सिस्टम को प्रदूषण से सुरक्षित रखने जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सैनिकों ने परमाणु रिएक्टर के मॉडल पर व्यावहारिक अभ्यास किया। दूसरी ओर, चीन के विदेश मंत्रालय ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फ़संबंधित आरोप पूरी तरह निराधार हैं। चीन ने दोहराया कि यूक्रेन युद्ध पर उसका रुख नहीं बदला है और वह खुद को शांति वार्ता का समर्थक तथा मध्यस्थ मानता है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय और क्रेमलिन ने इस रिपोर्ट पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि रॉयटर्स की रिपोर्ट सही साबित होती है, तो यह भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत की सेना आज भी बड़ी संख्या में रूसी रक्षा उपकरणों का उपयोग करती है।

पनामा नहर पर कब्जा कर रहा चीन, ट्रंप ने दी खुली चेतावनी, बोले- ऐसा कभी नहीं होने देंगे

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पनामा नहर और चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण सौंपकर बड़ी गलती की थी और अब चीन इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। उन्होंने यह बयान नॉर्थ डकोटा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया। इस दौरान उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता और राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी अपनी राय रखी।

ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपा तो उसके बाद वहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क कई गुना बढ़ा दिया गया। उनके अनुसार, इससे पनामा को भारी आर्थिक फायदा हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि अब चीन इस अहम समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों से जुड़ा यह मुद्दा किसी भी कीमत पर

नजरअंदाज नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है।

उनका दावा है कि चीन इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन को पनामा नहर पर नियंत्रण या प्रभाव स्थापित नहीं करने देगा। उन्होंने पनामा नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपने के पुराने फैसले को गलत बताया।

ट्रंप के अनुसार, नियंत्रण मिलने के बाद पनामा ने जहाजों से वसूले जाने वाले ट्रांजिट शुल्क में कई बार बढ़ोतरी की।

उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका के हितों को नुकसान हुआ और पनामा को आर्थिक फायदा मिला।

ट्रंप ने दोहराया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता अमेरिका के रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना है। पनामा नहर का मामला आखिर क्या है? आसान भाषा में समझिए पनामा नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इससे जहाजों को पूरे दक्षिण अमेरिका का लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ता और हजारों किलोमीटर की दूरी बच जाती है। दुनिया के व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इससे समय, ईंधन और परिवहन लागत कम होती है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है।

जन चौपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा,अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के दिए निर्देश

जल संरक्षण, स्वच्छता एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की भी दी गई जानकारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा के निर्देशानुसार आज जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरता में पंचायत भवन परिसर में जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा हितग्राहियों से सीधे संवाद कर उन्हें शीघ्र आवास निर्माण प्रारंभ करने एवं प्रगतिरत आवासों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जन चौपाल में अधिकारियों ने हितग्राहियों को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित एवं पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने हितग्राहियों से शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ लेते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा निर्धारित समयावधि में आवास पूर्ण करने का आग्रह किया। इस अवसर पर ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) तथा सोख्ता गड्ढों के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि वर्षा जल का संरक्षण भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीणों से जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने का भी आह्वान किया गया। जन चौपाल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ ग्राम के निर्माण को लेकर भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ग्रामीणों से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने और अपने गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहयोग करने की अपील की गई। कार्यक्रम में जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष, जिला समन्वयक, सहायक अभियंता, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जनसंचार शिक्षा व शोध में 'सेंटर ऑफएक्सीलेंस' की स्थापना

रायपुर/मूक पत्रिका

जनसंचार शिक्षा व शोध के क्षेत्र में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में होगी। कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल ने इसकी विस्तृत कार्य योजना पर अमल करने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार का विशेष दौरा किया। कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने गुजविप्रौवि के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई से हिसार में एक महत्वपूर्ण बैठक कर उच्च शिक्षा, जनसंचार और शोध को नई दिशा देने के लिए जनसंचार विभाग में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना पर सहमति बनी है। केटीयू, रायपुर (छत्तीसगढ़) और गुजविप्रौवि, हिसार (हरियाणा) के दोनों अग्रणी विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक सहयोग और शैक्षणिक उन्नयन पर विस्तृत मंथन किया गया।

जनसंचार में नया रोडमैप हेतु प्रो. दयाल ने समग्र विकास पर गहन चर्चा की। इसमें अकादमिक, रिसर्च और रणनीतिक बिंदुओं पर सहमति बनी। जनसंचार के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना पर जोर दिया गया। वैश्विक परिदृश्य और शिक्षण की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विभाग का उन्नयन होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करते हुए विद्यार्थी-केंद्रित और नवाचार आधारित अध्ययन प्रणाली को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही मीडिया इंडस्ट्री और अकादमिक क्षेत्र के बीच मजबूत तालमेल स्थापित करने की योजना बनी है।

जनसंचार शिक्षा और शोध के क्षेत्र में दोनों विश्वविद्यालयों के बीच एक मजबूत साझेदारी के लिए संयुक्त शोध परियोजनाएं तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों के आदान-प्रदान के नए अवसर बनेगें।

दो दिन की बारिश ने खोली नगर पालिका की तैयारियों की पोल, किसानों के चेहरे खिले तो शहरवासी हुए परेशान

मुंगेली /मूक पत्रिका

जुलाई के पहले सप्ताह में हुई बारिश ने जिले के किसानों के लिए राहत और खुशियों की सौगात लेकर आई है। पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश से खेतों में नमी पहुंचने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है और कृषि कार्यों में तेजी आ गई है। वहीं दूसरी ओर यही बारिश नगर क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई। शहर के कई वार्डों में जलभराव, कीचड़ और गंदगी ने नगर पालिका परिषद की बारिश पूर्व तैयारियों की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है।अमूमन हर वर्ष 15 जून के बाद से किसान खेतों की ओर रुख कर धान की बुआई और अन्य कृषि कार्य प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इस वर्ष मानसून की देरी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। बारिश समय पर नहीं होने से किसान लगभग 10 से 12 दिन पीछे हो गए थे। कई किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब लगातार दो दिनों से हुई बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त नमी आने लगी है, जिससे किसानों ने रोपा, जुताई और अन्य कृषि कार्य शुरू कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश होती रही तो फसल की स्थिति सामान्य हो सकती है।वहीं नगर क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई। हल्की से मध्यम बारिश में ही शहर के कई वार्डों की सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई। नालियों की समय पर सफाई नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर भर गया। कई मोहल्लों में घरों के सामने कीचड़ और गंदगी फैल गई, जिससे लोगों का पैदल निकलना तक मुश्किल हो गया। कई स्थानों पर जलभराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि हर वर्ष बारिश से पहले नगर पालिका द्वारा नालों और नालियों की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन पहली ही बारिश में इन दावों की हकीकत सामने आ जाती है।

डीएवी में मिली मजबूत नींव, सगे भाई-बहन ने रचा सफलता का इतिहास : बहन बनी सीए जिला टॉपर, भाई का आईआईटी रुड़की में चयन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता के लिए यह अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है कि विद्यालय के पूर्व छात्र-छात्रा सगे भाई-बहन ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से जिले एवं विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय की पूर्व छात्रा पलक महेश्वरी ने सीए फाउंडेशन परीक्षा-2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है, वहीं उनके सगे भाई वेदांश महेश्वरी का चयन देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आईआईटी रुड़की में हुआ है। दोनों भाई-बहनों की इस सफलता के पीछे डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता में प्राप्त मजबूत शैक्षणिक नींव और संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विद्यालय में अध्ययन के दौरान ही दोनों विद्यार्थियों ने अपनी मेधावी प्रतिभा का परिचय दिया था और विद्यालय तथा जिले के टॉपर के रूप में पहचान बनाई थी। डीएवी में मिली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, शिक्षकों का मार्गदर्शन और निरंतर प्रोत्साहन ने उनके भविष्य की मजबूत आधारशिला तैयार की, जिसका परिणाम आज राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इस बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया है।डी ए वी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक शिक्षण पद्धति, नैतिक मूल्यों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है। विद्यालय विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि यहां अध्ययन करने वाले विद्यार्थी लगातार बोर्ड परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर रहे हैं।इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य पी एल जायसवाल ने कहा,÷पलक महेश्वरी और उनके भाई की सफलता हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। दोनों विद्यार्थियों ने डीएवी में अध्ययन के दौरान जो मजबूत शैक्षणिक आधार प्राप्त किया, उसी के बल पर उन्होंने आज यह मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि बताती है कि सही मार्गदर्शन, अनुशासन और कठिन परिश्रम से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हमें विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी आगे भी विद्यालय, जिले और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करते रहेंगे।÷विद्यालय परिवार ने दोनों पूर्व छात्र-छात्रा को उनकी इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। यह सफलता एक बार फिर सिद्ध करती है कि डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता अपने विद्यार्थियों को मजबूत शैक्षणिक आधार प्रदान कर उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सशक्त मंच है।

अम्बेडकर वार्ड में 5.40 लीटर देशी मदिरा प्लेन के साथ आरोपी गिरफ्तार

मुंगेली /मूक पत्रिका

कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी उपनिरीक्षक विभाग की टीम ने नगर पालिका मुंगेली अंतर्गत अम्बेडकर वार्ड में कार्रवाई करते हुए रामसिंह खाण्डेकर के कब्जे से 5.40 लीटर देशी मदिरा प्लेन जब्त की। जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर साय ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और आरोपी लेखराम साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई सहायक आबकारी अधिकारी रविन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें आबकारी उपनिरीक्षक जयसिंह मरकाम सहित विभाग की टीम शामिल रही।

बिजली की आँख मिचौली से उपभोक्ताओं का हाल बेहाल, जैजैपुर स्टेशन का मामला, सुशासित तेवहार आयोजित कर जहाँ सुनी गई जनता की समस्या, वही की जनता बिजली कटौती से है त्रस्त, ओड़ेकरा

जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी उपभोक्ताओं कि समस्याओं का नहीं कर पा रहें निराकरण।

सक्ती/ जैजैपुर/मूक पत्रिका

जिले के जैजैपुर सबस्टेन अंतर्गत आने वाले ओड़ेकेरा फ़िटर में आधा दर्जन गांव लोग बीते चार दिन से बिजली विभाग के ख़राब कार्य प्रणाली से जूझ रहे है और ग्रामीण अंधेरे में डूबे हुए हैं। जिसका सुध लेने वाला कोई नहीं हैं, यहाँ सुधार के नाम पर उपभोक्ता को गुमराह किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के दिन रात शिकायत के बाद भी विभाग अपनी लापरवाही और नाकामी पे सुधार नहीं कर पा रहे हैं। बता दे बीते 4-5 दिनों से जैजैपुर सब स्टेशन के अंतर्गत के ओड़ेकेरा फीडर में लगातार खराबी आ रहा हैं जिससे कारण 6-7 के ग्रामीण उपभोक्ताओं का जीना मुश्किल हो गया। बीते 4-5 दिन से सुधार के नाम पर बस जिम्मेदार जिला अधिकारी सहित स्थानीय अधिकारी के द्वारा आश्वासन ही दिया जा रहा है। जबकि यह समस्या कोई नई नहीं हैं बीते 2-3 वर्ष से यहाँ की स्थिति जस के तस बनी हुई जिसका ख़ामियाज़ा हर साल ग्रामीण इलाकों हज़ारों उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा हैं। बता दें जिले के जैजैपुर सब स्टेशन के ओड़ेकेरा फ़ीडर में लगातार दो तीन वर्षों से बिजली गुल की समस्या लोग बेहद परेशान हैं। बेवजह बिजली कटौती में सुधार के नाम पर बिजली विभाग के स्थानीय जिम्मेदारों के द्वारा सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर उपभोक्ता एवं आला अधिकारियों के समक्ष वाहवाली लूट रहे। जबकि यहाँ की ज़मीनी हकीकत का आलम ये है की हल्की फुल्की हवा बारिश होने पर रात भर और दिन भर बिजली गुल रहती है।

गर्मी का मौसम हो तो ओवरलोडिंग और लोड सेटिंग के नाम पर घंटों घंटों भर बिजली कटौती किया जाता है। जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं क़ीमती दिन चरिया पर पड़ता है। जिसका बिजली विभाग को कोई सरोकार नहीं। ताजूब की बात यह है की बिजली विभाग के जिम्मेदारों को ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का लगातार शिकायत मिलने के बावजूद विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर उसका निस्तारण सुधार ना हो पाना लोगों के मानों में रोष और आक्रोश को दिन ब दिन पैदा कर रहा है।

जैजैपुर सब स्टेशन के सभी फीडर में से ओड़ेकेरा फीडर का कनेक्शन रहता है खराब - आप सभी को जान कर हैरत होगा की जैजैपुर सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सभी फीडर का बिजली कनेक्सन में फाल्ट आने पर सुधार कार्य कराकर विद्युत सप्लाई चालू करा दिया जाता है तो वही ओड़ेकेरा फीडर बीते दो-तीन साल से गर्मी या बरसात में लाईन का खराब होने पर घंटों घंटों तक सुधार नहीं हो पाता है और कहीं रात के समय बिजली सप्लाई ख़राब हो जाए तो यहाँ के ग्रामीणों का भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। सप्लाई ख़राब होने ट्रिपिंग आने और ब्रेकडाउन के नाम पर दिन रात भर बिजली बंद रहने का आरोप उपभोक्ता लगा रहे हैं। जिसका सुधार हो पाना भी संभव नहीं रहता है। ओड़ेकरा फ़िटर के उपभोगताओं कहना है यह समस्या बीते कई वर्षों से चल रहा हैं जिसका समाधान आज तक नहीं किया जा रहा है, बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फदिखावा करने का भी आरोप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों लगा रहे हैं। बीते दिनों मौसम ख़राब होने के कारण 4-5 दिन ओड़ेकेरा, बहेराडीह, जुनवानी, गाड़ामोर, कुटराबोड़, छिर्राडीह इत्यादि गांव के उपभोक्ता बेहद परेशान और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जिसके कारण लोगों के चेहरे पर स्थानीय बिजली विभाग के प्रति नाराजगी साफ़ दिखाई दे रहा है।

आरंग विधानसभा को मिलेगी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर/मूक पत्रिका

आरंग विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास और जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आगामी 6 जुलाई को नगर पंचायत समोदा में एक भव्य लोकार्पण एवं भूमिपूजन समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस महा-आयोजन को ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने सर्किट हाउस (सिविल लाइन, रायपुर) में अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं अन्य वरिष्ठ राजनेताओं के मुख्य आतिथ्य में होने वाले इस कार्यक्रम की सुरक्षा, बैठक व्यवस्था और अन्य प्रोटोकॉल को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई।

कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वरिष्ठ नेताओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए गरिमामय और भव्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर वाटरप्रूफ डोम, निर्बाध बिजली-पानी की आपूर्ति, वीआईपी मूवमेंट, और आम जनता के बैठने व आवागमन के लिए चाक-चौबंद इंतजाम करने के कड़े निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि÷आरंग विधानसभा क्षेत्र की जनता से किया गया विकास का हर वादा हमारी प्राथमिकता है। 6 जुलाई को समोदा में होने जा रहा यह कार्यक्रम क्षेत्र की प्रगति में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। जनसेवा और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही हमारा एकमात्र संकल्प है।÷समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देशः लोकार्पण और भूमिपूजन से जुड़े सभी विभागीय कार्यों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए गए।सुरक्षा और ट्रैफिक प्लानः कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और आमजन को कोई असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को रूट चार्ट तैयार करने को कहा गया है।

विभागीय समन्वयः लोक निर्माण विभाग (क्ल्ब्ह्ष), विद्युत विभाग, और स्थानीय प्रशासन को आपसी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी गई।इस भव्य आयोजन से आरंग विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है, जिससे क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।इस बैठक में क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन के आला अफसर और विभागीय प्रमुख मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।